RNI No. : TNHIN/2013/52520 ■ वर्ष - 13 ■ अंक - 259 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 17-04-2026 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 बंगाल में घुसपैठियों का स्वागत करती हैं ममता : हिमंत विश्व शर्मा

6 महिला आरक्षण बिल पर राजनीतिक तूफान

7 'कॉकटेल-2' के सेट पर रश्मिका मंदाना की मस्ती

फर्स्ट टेक

पाकिस्तान को सऊदी अरब से दो अरब डॉलर की सहायता मिली

कराची/भाषा। पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक एसबीपी ने सऊदी अरब से दो अरब अमेरिकी डॉलर की राशि मिलने की बृहस्पतिवार को पुष्टि की। वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने एक दिन पहले ही तीन अरब डॉलर की विदेशी सहायता मिलने की घोषणा की थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने बयान में कहा कि सऊदी अरब से दो अरब डॉलर की राशि 15 अप्रैल, 2026 को प्राप्त हुई। यह राशि ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना हुआ है। इस राशि का हस्तांतरण प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के दौरान हुआ, जहां वह पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए गए हैं।

पाकिस्तानी नौसेना ने जहाज से दागी जाने वाली एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया

कराची/भाषा। पाकिस्तान की नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित जहाज से दागी जाने वाली एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह विस्तारित दूरी पर लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है। सेना ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सेना की मीडिया इकाई इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में कहा कि मिसाइल अत्याधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली और उन्नत गतिशीलता से लैस है। यह प्रणाली इसे ''खतरों से बचने, बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने और सटीकता के साथ वार करने'' में सक्षम बनाती है। बयान में कहा गया, ''पाकिस्तान नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित और जहाज से दागी जाने वाली एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया और लंबी दूरी पर उच्च गति के साथ सटीक रूप से अपने लक्ष्य को भेदा।''

यूक्रेन के साहस के सम्मान में जेलेंस्की को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया

मिडलबर्ग/एपी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को बृहस्पतिवार को एक समारोह में प्रतिष्ठित 'इंटरनेशनल फोर फ्रीडम अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। जेलेंस्की को यह पुरस्कार रूस द्वारा चार वर्ष से अधिक समय पहले शुरू किए गए युद्ध के जवाब में उनके और उनके देश के साहस और दृढ़ता के लिए दिया गया। यह सम्मान रूजवेल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। रूजवेल्ट फाउंडेशन की स्थापना 1982 में की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने 1941 के अपने एक भाषण में चार तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया था।

16-04-2026 सूर्यास्त 6:32 बजे | 17-04-2026 सूर्योदय 6:05 बजे

BSE	NSE
77,988.68	24,196.75
(-122.56)	(-34.55)

सोना	चांदी
16,018 रु.	258,411 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

दाल में काला

यदि संतुष्ट नहीं उत्तर से,
प्रश्न पूछने वाला है।
बारबार कहने पर भी जब,
उत्तर को यदि टाला है।
गोलमोल करके उत्तर को,
यदि प्रति प्रश्न उछाला है।
तब यह बात समझ लेना सब,
वहां दाल में काला है।।

प्रधानमंत्री ने तनावपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच स्थायी शांति की अपील की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुनिया एक 'बेहद तनावपूर्ण' स्थिति से गुजर रही है, जिससे सभी देश प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति लाने की अपील की, क्योंकि सैन्य संघर्ष से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ व्यापक वार्ता के बाद यह टिप्पणी की, जिसमें व्यापार, रक्षा और अवसंरचना के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अपनी वार्ता में, मोदी और स्टॉकर ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन में संघर्षों के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें कम करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प लिया।

ऑस्ट्रिया के चांसलर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से चार दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे। भारत की यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मीडिया बयान में कहा, ''पूरी दुनिया बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रही है। और यह स्थिति हम सब को प्रभावित कर रही है।'' उन्होंने कहा, ''ऐसे तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में, भारत और ऑस्ट्रिया इस बात पर एकमत हैं कि सैन्य संघर्ष से समस्याओं का हल नहीं हो सकता। चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम एक स्थिर, टिकाऊ और स्थायी शांति का समर्थन करते हैं।

इजराइल और अमेरिका का लक्ष्य 'एक जैसा', हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार : नेतन्याहू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

यरूशलम/भाषा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ जारी संघर्ष में इजराइल और अमेरिका के लक्ष्य एक जैसे हैं। नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि अमेरिका, ईरान के साथ अपने संपर्कों की जानकारी इजराइल को देता रहा है।

उन्होंने दोहराया कि अमेरिका और इजराइल ईरान की संवर्धन क्षमताओं को समाप्त करने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को फिर से खोलने के लिए प्रयासरत हैं। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, हमारे और अमेरिका के लक्ष्य एक जैसे हैं। हम ईरान से परमाणु सामग्री को हटाना चाहते हैं, हम ईरान के भीतर संवर्धन क्षमताओं को खत्म होते देखना चाहते हैं और निश्चित रूप से हम जलडमरूमध्य को खुलते देखना चाहते हैं।

उन्होंने ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच 22 अप्रैल को समाप्त होने वाले दो सप्ताह के युद्धविराम का जिक्र करते हुए कहा, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस मामले का क्या अंजाम होगा या यह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। लड़ाई दोबारा शुरू होने की संभावना को देखते हुए, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं।

नेतन्याहू ने इजराइली सेना और शिया लेबनानी समूह हिजबुल्ला के बीच भारी गोलाबारी पर कहा कि सेना उत्तरी इजराइल के निवासियों के साथ खड़ी रहते हुए चरमपंथी ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा, मैं उत्तर के निवासियों के साथ खड़ा हूं जो दृढ़ संकल्पित हैं। साथ ही हमारी सेनाएं हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हुए हैं।

जनता दर्शन

मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या गुरुवार को बेंगलूरु स्थित कावेरी सीएम आवास में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए।

ईरान-अमेरिका वार्ता के दूसरे दौर की तारीख अभी तय नहीं : पाकिस्तान

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दूसरे दौर के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का यह बयान उन खबरों के बीच आया है कि पाकिस्तानी पक्ष द्वारा ईरानी नेतृत्व सहित क्षेत्रीय नेताओं के साथ किए गए हालिया संपर्क के बाद बातचीत का एक और दौर संभव है। अंद्राबी ने बातचीत के दूसरे दौर की संभावना को खारिज करने से परहेज करते हुए कहा, अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। बातचीत के दूसरे दौर के लिए प्रतिनिधिमंडलों के आगमन और इसके स्वरूप के बारे में पूछे जाने पर अंद्राबी ने कहा, कौन आएगा, प्रतिनिधिमंडल कितना बड़ा होगा, कौन रुकेगा और कौन जाएगा – यह दोनों पक्षों को तय करना है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से किया आग्रह

अपनी मातृभाषा के अलावा कम से कम एक भारतीय भाषा सीखें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वर्धा/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण केवल देश की मूल भाषाओं की नींव पर ही किया जा सकता है। मुर्मू ने कहा कि भारत की सभी विविध भाषाओं में संस्कृति, संवेदनशीलता और चेतना की एक ही धारा बहती है। उन्होंने लोगों से अपनी मातृभाषा के अलावा कम से कम एक भारतीय भाषा सीखने की अपील की।

राष्ट्रपति महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा, ''भारत की आत्मा भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति पाती है तथा हमारी सभी विविध भारतीय भाषाओं में संस्कृति, संवेदनशीलता और चेतना की एक ही धारा बहती है।''

राष्ट्रपति ने कहा, ''यही कारण है कि मैं या मेरे जैसे अन्य ओडिया भाषी, हिंदी में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों या महादेवी वर्मा की कविताओं के ओडिया अनुवाद पढ़ते समय उनसे सहजता से जुड़ सकते हैं। इसी तरह, हिंदी पाठक, फकीर मोहन सेनापति, गोपीनाथ मोहंती और प्रतिभा रे जैसे ओडिया साहित्यकारों से जुड़ते हैं।

आंध्र प्रदेश में सड़क दुर्घटना में आठ श्रद्धालुओं की मौत

चिलकलदोना (आंध्र प्रदेश)/भाषा। आंध्र प्रदेश में कुरनूल जिले के मंत्रालयम में बृहस्पतिवार को एक वाहन की टैंकर से टक्कर हो जाने पर पांच महिलाओं समेत कम से कम आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे को बेहद पीड़ादायक बताया। मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।''

अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु श्री राघवेंद्र स्वामी मठ में दर्शन करने के लिए वाहन से मंत्रालयम जा रहे थे। उन्होंने कहा कि वाहन में करीब 20 यात्री थे और वह (वाहन) टैंकर से टकरा गया।

लाहौर में हुए हमले में लश्कर-ए-तैयबा का सह-संस्थापक घायल

लाहौर/भाषा। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकी समूह का सह-संस्थापक आमिर हमजा बृहस्पतिवार को लाहौर में मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। हमजा को लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नेता माना जाता है। सईद आतंकी वित्तपोषण मामलों में कई वर्षों की सजा के बाद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। पुलिस के अनुसार, अज्ञात बंदूकधारियों ने गृह मंत्री मोहसिन नकवी के स्वामित्व वाले निजी टीवी चैनल '24 न्यूजएचडी टीवी' के वाहन पर गोलीबारी की। चैनल के धार्मिक कार्यक्रम के मेजबान न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) नजीर अहमद गाजी और हमजा वाहन में सवार थे। पुलिस ने बताया, ''लाहौर के पेको रोड पर टीवी चैनल के कार्यालय के पास, मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात हथियारबंद लोगों ने कार पर गोलियां चलाईं जिसमें गाजी और हमजा सवार थे।

अगर संसद में परिसीमन विधेयक पारित होता है तो इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे : द्रमुक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि परिसीमन विधेयक संसद से पारित होता है, तो वह इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार गीत जारी करते हुए द्रमुक के विधि विभाग के सचिव एन. आर. इलंगो ने कहा कि कानूनी विकल्प हमेशा खुला है। उन्होंने कहा, हम दक्षिणी राज्यों के हित में कानूनी कदम उठाएंगे।

हालांकि, उन्होंने विधेयक के संसद से पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने पर संदेह जताया।

इलांगो के बयान का समर्थन करते हुए पार्टी के संगठन सचिव आर. एस. भारती ने कहा, हमें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हमारे पास अदालत जाने के लिए ठोस आधार मौजूद हैं।

संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए आश्वासन पर उन्होंने कहा, सिर्फ मौखिक आश्वासन भरोसा नहीं जगाते। विधेयक में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी तरह की ठोस गारंटी नहीं दी गई है। भारती ने दावा किया कि परिसीमन विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के पास 80 से अधिक सांसद हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नोटबंदी के फैसले का जिक्र करते हुए भारती ने इसे पूरी तरह विफल बताया और कहा कि सरकार इससे काला धन निकालने में नाकामयाब रही। उन्होंने कहा, इसी तरह परिसीमन की प्रक्रिया भी नाकाम होगी। इससे दक्षिणी राज्यों के हित प्रभावित होंगे और उत्तर तथा दक्षिण के बीच नए विवाद खड़े हो सकते हैं।

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू हुआ : अधिसूचना

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 बृहस्पतिवार से लागू हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालांकि, यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया। कानून को लागू करने के संबंध में एक अधिकारी ने ''तकनीकी खामियों'' का हवाला दिया, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। अधिकारी ने कहा कि हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन मौजूदा सदन में आरक्षण को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकता है। अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि घोषित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

मंत्री नितेश राणे ने किया 'कॉर्पोरेट जिहाद' का दावा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने राज्य में कॉर्पोरेट जिहाद सामने आने का दावा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि जिहादी गतिविधियों को रोकने के लिए नौकरियों में केवल हिंदू उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना समय की मांग है।

उनकी यह टिप्पणी नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की एक बीपीओ यूनिट में कथित धर्मांतरण के प्रयासों और यौन उत्पीड़न के मामलों के संदर्भ में आई है।

पुलिस ने इस मामले में टीसीएस के आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सात पुरुष और एक महिला प्रबंधक शामिल हैं। एक अन्य महिला कर्मचारी फरार है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच के लिए एक तथ्य-अन्वेषण समिति गठित की है।

नासिक के टीसीएस मामले का हवाला देते हुए राणे ने आरोप लगाया कि नौकरियों का इस्तेमाल धर्मांतरण के साधन के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, यदि व्यापार से लेकर कॉरपोरेट कार्यालयों तक हर मंच का उपयोग हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, तो इसका कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाओं के कारण हिंदू समुदाय में यह भावना बढ़ रही है कि आर्थिक लेन-देन और रोजगार केवल अपने समुदाय के लोगों के साथ ही किए जाएं।

मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि कंपनियां भविष्य में ऐसी जिहादी गतिविधियों को रोकने के लिए केवल हिंदुओं को नौकरी देने की नीति अपना सकती हैं। उन्होंने कहा, हम समाज को बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जमीनी अनुभवों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यदि रोजगार का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जाता है, तो हिंदू उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना 'हिंदू राष्ट्र' को मजबूत करने के लिए समय की मांग है।

जनगणना जातियों की गिनती के साथ हो रही है, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया जारी है और जातियों के साथ ही यह जनगणना होगी। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण गैर-संवैधानिक है।

लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से संबंधित तीन विधेयकों को पेश किए जाते समय समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव की कुछ टिप्पणियों का जवाब देते हुए शाह ने ये बातें कहीं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में आज 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' पेश किए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया।

विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इन विधेयकों के माध्यम से जिस तरह परिसीमन को जनगणना से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक में पिछड़े वर्गों और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल किया कि सरकार को विधेयक लाने की इतनी जल्दीबाजी क्या है? उन्होंने कहा, ''आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? जैसे ही जनगणना होगी, हम जातीय जनगणना की मांग करेंगे, जातीय जनगणना होगी तो हम आरक्षण की मांग करेंगे। इसलिए आप यह धोखा देना चाहते हैं।''

अमित शाह ने कहा कि सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है और सपा सदस्यों के कुछ बयान जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ''अखिलेश यादव ने कहा कि जनगणना क्यों नहीं हो रही है? मैं बताना चाहता हूं कि देश में जनगणना शुरू हो चुकी है और जारी है।''

शाह ने कहा कि सपा अध्यक्ष ने जातीय जनगणना की बात कही ''तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जातियों की जनगणना का निर्णय पहले ही ले चुकी है और जाति के साथ ही यह जनगणना हो रही है।''

महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने मनाया अपनी स्थापना का 'रजत जयंती' समारोह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के पद्मनाभनगर स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल के प्रांगण में गुरुवार को अस्पताल का रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सुभाष बंसल, अस्पताल के अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद गोयल, पूर्व अध्यक्ष सुभाष गोयल, गवर्निंग बोर्ड के सदस्य चंद्रप्रकाश रामसिसरिया, रमेश भाऊवाला, रतनलाल सिंघल, मदनलाल अग्रवाल, विक्रम अग्रवाल, सांवरमल अग्रवाल एवं अन्य ट्रस्टियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।ङ्कङ्कअध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद गोयल ने सभी का स्वागत करते हुए अस्पताल की गतिविधियों की जानकारी दी। गोयल ने बताया कि लोगों की सेवा करते हुए अग्रसेन अस्पताल को आज पूरे 25 वर्ष हो गए हैं और इन वर्षों में अस्पताल ने समाज में जो स्थान बनाया है उसका सारा श्रेय अस्पताल के डाक्टरों व स्टॉफ को जाता है। उन्होंने अस्पताल के सभी डाक्टरों व कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए सभी को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। गोयल ने अस्पताल में सहयोग देने वाले सभी दानदाताओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अग्रसेन अस्पताल की रीढ़ की हड्डी हैं यह दानदाता। कार्यक्रम के अंत में सभी को धन्यवाद दिया गया।

लोकसभा में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा : अमित शाह

नई दिल्ली/भाषा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी हिस्सेदारी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी चुनाव मौजूदा व्यवस्था के तहत ही होंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पर चर्चा में कुछ विपक्षी सदस्यों की विभिन्न आशंकाओं और आपत्तियों को खारिज करते हुए शाह ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वह विधेयकों पर चर्चा का जवाब शुक्रवार को विस्तार से देंगे, लेकिन कुछ भ्रांतियों को अभी दूर करना चाहते हैं। शाह ने कहा कि ऐसी धारणा पैदा की जा रही है कि इन तीनों विधेयकों के पारित होने से दक्षिण राज्यों की संख्या लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और उन्हें बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि कर्नाटक में अभी 28 लोकसभा सीट हैं जो कुल 543 सीट का 5.15 प्रतिशत हैं, लेकिन ये विधेयक पारित होने के बाद कर्नाटक के सदस्यों की संख्या 42 हो जाएगी जो कुल 816 सीटों का 5.14 प्रतिशत होगी। शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश में अभी 25 लोकसभा सीट हैं और उसका प्रतिनिधित्व 4.6 प्रतिशत है जो परिसीमन के बाद 38 (4.65 प्रतिशत) हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मौजूदा सीट की संख्या 17 (3.13 प्रतिशत) है, जो बाद में 26 (3.18 प्रतिशत) हो जाएंगी।

शाह ने कहा, मैं तमिलनाडु की जनता को आश्वस्त करना चहता हूं कि उनके प्रतिनिधित्व में भी कोई कमी नहीं आएगी और राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य के 39 सदस्य (7.18 प्रतिशत) हैं जो परिसीमन के बाद 59 (7.23 प्रतिशत) हो जाएंगे।

शाह ने कहा कि लोकसभा में अभी केरल का प्रतिनिधित्व 6.38 प्रतिशत है जो बढ़कर 3.67 प्रतिशत (30 सीट) हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर अभी दक्षिणी राज्यों से 129 लोकसभा सदस्य आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व 23.76 प्रतिशत है, जो 50 प्रतिशत वृद्धि के बाद 195 सीट और 23.97 प्रतिशत यानी 24 प्रतिशत हो जाएगा।

शाह ने कहा, इसलिए प्रतिनिधित्व कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है।

परिसीमन आयोग में पक्षपात की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा की आशंकाओं पर शाह ने कहा, मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूं कि हमने परिसीमन आयोग अधिनियम में कोई बदलाव नहीं किया है। पूरी तरह आपके कानून को रिपीट किया है। उन्होंने कहा, आपने उस समय (कांग्रेस की सरकार में) इस अधिनियम का इस्तेमाल कर अगर हेरफेर की होगी तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। और कुछ नहीं कह सकता।

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फायदे के लिए इन विधेयकों को इस समय लाए जाने के आरोपों पर शाह ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट संसद की स्वीकृति और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगी। 2029 से पहले इसके लागू होने का सवाल नहीं है। तब तक सारे चुनाव पुरानी व्यवस्था से होंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि वह जीतेंगे नहीं, यह अलग बात है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ की आबादी को प्रभावित करने के आरोप लगाने वाले लोग हमारी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, लोकतंत्र में जनता तय करती है। राजनीतिक दल यह नहीं कर सकते। अगर कर पाते तो हम तो जीतते ही नहीं, क्योंकि आप सत्ता में बैठे थे।

अंबेडकर जन्मोत्सव

बेंगलूरु के भारत रत्न डॉक्टर बीआर अंबेडकर दलित हितरक्षण समिति द्वारा गोविंदराज नगर में डॉ अंबेडकर जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में महेंद्र मुणोत ने बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कहा कि संविधान से ही हमें समानता का अधिकार मिला है। हमें अपने संविधान पर गर्व है, संविधान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। समिति के सदस्यों ने मुणोत को सम्मानित किया।

द्रमुक सांसदों के काले परिधानों पर प्रधानमंत्री का कटाक्ष

'काला टीका' लगाने के लिए आपका धन्यवाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों का विरोध करने के लिए लोकसभा की कार्यवाही में काले कपड़े पहनकर शामिल हुए द्रमुक सांसदों पर निशाना साधा और कहा कि यह बुरी नजर से बचाने के लिए 'काला टीका' लगाने जैसा है। लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', परिसीमन विधेयक, 2026' और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पर अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ''मैं हल्के-फुल्के अंदाज में कुछ कहना चाहूंगा।''

मोदी ने द्रमुक सांसदों के काले कपड़ों और काले झंडों का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा, हरेक के अपने राजनीतिक करण होते हैं। पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। अपने यहां जब भी कोई शुभ काम होता है तो उसे नजर नहीं लग जाए, इसके लिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए।

द्रमुक सांसद जहां लोकसभा में काले परिधान पहनकर आए, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष एम के स्टालिन ने राज्य में एक चुनावी रैली के दौरान काला झंडा लहराया और परिसीमन विधेयक को काला कानून' करार देते हुए उसकी प्रति जलाई। इसके बाद द्रमुक के नेताओं, राज्य के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने घरों, पार्टी दफ्तरों पर काले झंडे लगाए।

प्रदर्शन

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों ने गुरुवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण बिल में एससी एसटी आरक्षण को शामिल करने की अपनी कथित मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

आंध्र प्रदेश विस्फोट मामले में 150 जिलेटिन की छड़ें फटने से स्थिति घातक हुईः पुलिस

कम्मलावांडला पल्ली (आंध्र प्रदेश)/भाषा। आंध्र प्रदेश के कम्मलावांडला पल्ली में बुधवार को हुआ विस्फोट, गैस चूल्हे में आग लगने के बाद 150 जिलेटिन की छड़ें फटने के कारण अत्यंत घातक हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई थी जबकि 29 अन्य घायल हो गए। विस्फोट के कारण दो घर दो घर पूरी तरह से ढह गए जबकि चार घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा।

श्री सत्यसाई जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस. सतीश ने बताया कि दो कमरों वाले घर में वेंकन्ना (55) नामक व्यक्ति चाय बना रहा था तभी गैस चूल्हे में हुई एक अजीब दुर्घटना के कारण भीषण विस्फोट हुआ।

आग कैसे लगी, इसका ब्योरा देते हुए सतीश ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, वेंकन्ना गैस चूल्हे पर चाय बना रहा था तभी चूल्हे और सिलेंडर को जोड़ने वाली पाइप टूट गई। पाइप स्टोव की तरफ से टूट गई और गैस लीक होने लगी। उन्होंने बताया कि आग धीरे-धीरे और तेज होती गई, जिसके कारण गर्मी से दबाव बनने लगा और परिणामस्वरूप जिलेटिन की छड़ें एक-एक करके फट गईं। एसपी ने बताया कि वेंकन्ना ने गैस रिसाव को नियंत्रित करने और ट्यूब को फिर से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा और इस प्रयास में वह घायल भी हो गया। घटना के बाद वेंकन्ना और उनके परिवार के छह अन्य सदस्य मौके से भाग गए।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने गुलाबी डिब्बे में रखी जिलेटिन की छड़ की मौजूदगी के बारे में कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने कहा कि सात सदस्यीय परिवार वहां बच निकलकर भागने में सफल रहा जिसमें दो नाबालिग पोते-पोतियां भी शामिल थे। हालांकि घटना के बाद आग बुझाने के लिए वहां जुटे 50 लोग और पड़ोसी विस्फोट की चपेट में आ गए।

पुलिस के अनुसार, वेंकन्ना लगभग एक दशक पहले पड़ोसी राज्य तेलंगाना से पलायन कर आया था। वह ट्रैक्टर से जुड़ी ड्रिलिंग मशीन से बड़े-बड़े पत्थरों और चट्टानों में विस्फोट करके अपना जीवन यापन करता था और इस प्रक्रिया में चट्टानों को तोड़ने के लिए जिलेटिन की छड़ों का उपयोग करता था।

सतीश ने कहा कि वेंकन्ना जैसे श्रमिकों की जिलेटिन की छड़ तक पहुंच मुमकिन नहीं है। जिलेटिन की छड़ें आमतौर पर उन्हें सड़क परियोजनाओं और कृषि क्षेत्रों से पत्थरों को हटाने जैसे कार्यों में लगे ठेकेदार लागत के आधार पर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वेंकन्ना ने ऑर्डर पूरा होने के बाद कम से कम 10 से 15 शेष जिलेटिन की छड़ को एकत्र करना शुरू कर दिया, जिससे पिछले आठ से नौ महीनों में उसने लगभग 150 जिलेटिन की छड़ का अवैध रूप से भंडारण कर लिया था। उन्होंने कहा कि अशिक्षित वेंकन्ना जिलेटिन की छड़ों से होने वाले घातक खतरे से अनजान था।

उसे सिर्फ यही पता था कि जिलेटिन की छड़ों को केवल फ्यूज और डायनेमो द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है जबकि वास्तव में गर्मी और दबाव ने घर में हुए तत्काल विस्फोट में भूमिका निभाई थी।

महिला आरक्षण और परिसीमन संबंधी विधेयक पारित हुआ तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा: प्रियंका

नई दिल्ली/भाषा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सत्ता बनाए रखने के लिए बहाने के तौर पर उपयोग करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि यदि परिसीमन के प्रावधान वाला विधेयक पारित हो गया तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के वर्तमान संख्याबल 543 के आधार पर महिला आरक्षण को लागू करना चाहिए और जाति जनगणना के बिना परिसीमन नहीं होना चाहिए। प्रियंका ने अपने भाषण के दौरान, गृह मंत्री अमित शाह के हंसने का उल्लेख किया और हुए उन पर तंज कसते हुए कहा, गृह मंत्री हंस रहे हैं, पूरी योजना बना रखी है...यदि आज चाणक्य जिंदा होते तो चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पर। गृह मंत्री जी हंस रहे हैं, मेरी बात से सहमत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने इस वर्ग-उस वर्ग की बात कर ओबीसी के विषय को हल्के में लिया, जो उचित नहीं है।

कांग्रेस सांसद ने सवाल किया, क्या प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना से घबरा रहे हैं कि जब असल आंकड़ें आएंगे तो पता चलेगा कि ओबीसी वर्ग कितना बड़ा और कितना मजबूत है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह विधेयक लाई है क्योंकि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भागीदारी नहीं देना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा, 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी वर्ग का हक छीनना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस राजनीति की बू का जिक्र किया, वह इस विधेयक में पूरी तरह घुली हुई है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, अगर आप (प्रधानमंत्री) महिलाओं का सम्मान करते हैं तो महिलाओं का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करते तथा यह कदम आपके पद और गरिमा के अनुकूल नहीं है।

केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा, अगर प्रधानमंत्री ने यह ऐतिहासिक कदम ईमानदारी से उठाया होता तो पूरा सदन इसका समर्थन करता। कांग्रेस महासचिव ने इस बात का उल्लेख किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि महिला आरक्षण को 2029 से लागू किया जाए, जो अब सरकार करने की बात कर रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, प्रधानमंत्री यहां (सदन में) भले ही राहुल जी का मजाक बनाते हैं, लेकिन घर जाकर उनकी बातों पर गौर करते हैं।

प्रियंका ने महिला आरक्षण के ऐतिहासिक प्ररिप्रेक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना एक अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में संसद में पेश किया था। लेकिन उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाए।

ऋषिकेश के पशुलोक गंगा बैराज में सी-प्लेन के संचालन का पर्यावरणविद ने विरोध किया

ऋषिकेश/भाषा

पर्यावरणविद विनोद प्रसाद जुगलान ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकेश स्थित पशुलोक गंगा बैराज जलाशय में सी-प्लेन उतारे जाने का विरोध करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इससे न केवल पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े कार्यों में बाधा पैदा होगी, बल्कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा।

नमामि गंगे परियोजना की देहरादून जिला समिति के सदस्य जुगलान ने कहा कि सी-प्लेन संचालन पर्यावरण संरक्षण के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा, यहां मगरमच्छ, खतरे की जद में आ चुकी नस्लों में सूचीबद्ध गैंगेटिक डॉल्फिन और गोल्डन महाशीर बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। सी-प्लेन के संचालन से पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में न केवल बाधा उत्पन्न होगी, बल्कि स्थानीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से मानव वन्यजीव टकराव बढ़ेगा।

जुगलान ने कहा कि सी-प्लेन के उड़ान भरने और उतरने के दौरान उसके इंजन से उत्पन्न तीव्र हलचल एवं शोर से गैंगेटिक डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुओं तथा गोल्डन महाशीर सहित कई जलीय जीवों का जीवन चक्र बुरी तरह से प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि इससे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के उन वन्यजीवों की जीवनचर्या पर भी असर पड़ेगा, जो यहां हर दिन अपनी प्यास बुझाने आते हैं।

जुगलान ने आशंका जताई कि जब जंगली हाथियों को यहां पानी पीने में दिक्कत होगी, तो वे इधर-उधर भटकेंगे, जिससे नीलकंठ महादेव को जाने वाले मार्ग पर आवागमन प्रभावित होगा और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ेंगी।

तीर्थाटन के विकास पर जोर देते हुए

पर्यावरणविद ने कहा कि गंगा सिर्फ नदी मात्र ही नहीं, हमारी पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर है और सी-प्लेन के जरिये इसे साहसिक पर्यटन स्थल में बदलने से दुनियाभर के करोड़ों लोगों की आस्था भी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि स्कंद पुराण के केदार खंड में ऋषिकेश और यहां की कई नदियों का जिक्र है, लेकिन इनमें से कई जैसे रंभा, चंद्र भागा और सरस्वती नदियां उपेक्षा के कारण पहले ही अपना स्वरूप खो चुकी हैं।

सरकार से सी-प्लेन के संचालन की योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए जुगलान ने कहा कि इसे स्थगित कर देना चाहिए, ताकि यहां के स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र एवं इसमें जीवित रहने वाले जीवों को बचाया जा सके।

पशुलोक गंगा बैराज जलाशय में छह अप्रैल को सी-प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई। राज्य सरकार का मानना है कि सी-प्लेन सेवा शुरू होने से चारधाम यात्रा, साहसिक पर्यटन और सप्तहांत यात्रा को बढ़ावा मिलेगा और देश-विदेश से आने वाले पर्यटक अब कम समय में सीधे ऋषिकेश व आसपास के प्रमुख स्थलों तक पहुंच सकेंगे, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

सरकार की योजना भविष्य में इस सेवा को टिहरी झील, नैनीताल झील और अन्य जलाशयों तक विस्तार देने की है, ताकि उत्तराखंड देश का प्रमुख सी-प्लेन गंतव्य बन सके।

बच्चे को तेजाब पिलाने के आरोप में महिला पर मामला दर्ज

हैदराबाद/भाषा। हैदराबाद में एक महिला पर परिवार की दूसरी बहू के चार साल के बेटे को तेजाब पिलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। महिला इस बात से ईर्ष्याग्रस्त थी कि ससुराल वाले उसके बेटे के बजाय उक्त पुत्रवधू के बच्चे पर अधिक ध्यान दे रहे थे। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आरोपी महिला और पीड़ित लड़के की मां की शादी एक ही परिवार में दो भाइयों से हुई थी। दोनों बहुएं संयुक्त परिवार में साथ रह रही थीं। लड़के की मां ने बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि आरोपी महिला ने उसके बेटे को जान से मारने के इरादे से फलों का रस पिलाने के बहाने रसोई में ले जाकर उसे तेजाब पिला दिया। आरोपी ने लड़के को चॉकलेट देने का वादा करके 'जूस' पीने के लिए ललचाया। मेडिपल्ली थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तेजाब पीने के बाद लड़का बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में उसे छुट्टी दे दी गई।

परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को नहीं पड़ेगा कोई फर्क : तमिलिसाई सुंदरराजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने उन सभी आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि परिसीमन की वजह से दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाएगा। भाजपा नेता ने गुरुवार को साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। परिसीमन की वजह से दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व को किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खुद सामने आकर इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, उन्होंने परिसीमन के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एमके स्टालिन संसद परिसर में परिसीमन के विरोध में काले कपड़े पहनकर दाखिल हो रहे हैं। मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि इससे उन्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इससे उनके हाथ खाली ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले इसी मुख्यमंत्री ने ताजमहल के प्रकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर मुख्यमंत्री को इस विरोध प्रदर्शन से क्या अर्जित हो गया। जवाब साफ है कि कुछ भी अर्जित नहीं हुआ।

तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि आज की तारीख में तमिलनाडु की स्थिति कैसी है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति किसी से छुपी नहीं है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल ना के बराबर है। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। इसके विपरीत, वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए परिसीमन के मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

भाजपा नेता ने दावा किया कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वो ऐसे मुद्दों का जिक्र प्रदेश की राजनीति में कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। उधर, केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि परिसीमन से दक्षिण के राज्य बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा, उन्होंने डीएमके पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि द्रमुक ने ही हमेशा से यह कोशिश की है कि कोई भी तमिल नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो पाए। मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से जुड़े विषयों को लेकर हमेशा से चिंतित रहते हैं। आप उनकी चिंता का अंदाजा महज इसी से लगा सकते हैं कि वो करीब 24 बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। इससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे तमिलनाडु को लेकर कितना फायदा चाहते हैं।

स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की प्रति जलाई, इसे 'काला कानून' बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नामक्कल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को परिसीमन विधेयक की एक प्रति जलाकर उसे ''काला कानून'' करार दिया और आरोप लगाया कि यह विधेयक तमिल लोगों को उनकी अपनी ही भूमि में ''शरणार्थी'' बनाने का प्रयास है। महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम पर संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक से कुछ घंटे पहले स्टालिन ने काला झंडा दिखाया, केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई परिसीमन विधेयक की एक प्रति जलाई और नारे लगाए। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के सिलसिले में पश्चिमी तमिलनाडु के नामक्कल में हैं और वहां उन्होंने विधेयक की प्रति जलाई।

स्टालिन और काले वस्त्र पहने अन्य लोगों ने इस बीच नारे लगाए। उन्होंने ''पोराडावोम, वेलवोम ओन्द्रगा'' (आइए हम मिलकर संघर्ष करें, साथ मिलकर जीतें) का नारा भी लगाया। स्टालिन द्वारा विधेयक की प्रति जलाने के बाद पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विधेयक की प्रतियां जलाईं। उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मदुरै में विधेयक की एक प्रति जलाई। उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि परिसीमन केंद्र सरकार के हाथों में राज्य के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को खत्म करने का एक हथियार है।

तमिलनाडु के साथ लगातार विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए उदयनिधि ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र कुछ उत्तरी राज्यों की मदद से अपनी मनमानी करने की सोच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र संसद में दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करना चाहता है।

उपमुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, ''अपने आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु की धरती भाजपा के अहंकार के आगे कभी नहीं झुकेगी... पार्टी प्रमुख द्वारा प्रज्वलित अधिकारों की यह अग्नि पूरे भारत में फैले।'' द्रमुक के राज्य मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' में पार्टी नेताओं आर.एस. भारती और टी.के.एस. एलंगोवन के नेतृत्व में काले कपड़े पहने पार्टी कार्यकर्ताओं ने परिसीमन विधेयक की प्रतियां जलाईं।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के. सेल्वपेरुंथगई ने सेलम में काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की निंदा की। द्रविड़र कषगम (डीके) के प्रमुख के. वीरमणि ने काला झंडा दिखाया और विधेयक की एक प्रति जलाई। डीके तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक का वैचारिक रूप से मातृ संगठन है। द्रमुक की सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने भी परिसीमन प्रक्रिया के विरोध में काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

एक बयान में स्टालिन ने कहा, विरोध की ज्वाला पूरे तमिलनाडु में फैले। फासीवादी भाजपा का घमंड चकनाचूर हो। तब, तमिलनाडु से उठी हिंदी थोपने के खिलाफ प्रतिरोध की आग ने दिल्ली को झुलसा दिया था। वह तभी शांत हुई जब उसने दिल्ली को झुकने पर मजबूर कर दिया। उनका इशारा स्पष्ट रूप से राज्य में 1960 के दशक में हुए हिंदी विरोधी आंदोलन की ओर था। उन्होंने कहा, ''आज मैंने इस काले कानून की प्रति जलाकर और काला झंडा दिखाकर उस आग को फिर से प्रज्वलित कर दिया है। यह आग अब पूरी द्रविड़ भूमि में फैलेगी। यह भड़केगी, यह प्रचंड होगी और यह भाजपा के अहंकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी।''

टीवीके प्रमुख विजय ने चुनाव घोषणापत्र जारी किया

महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक सहायता देने का वादा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें खासतौर पर महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया है। घोषणापत्र में 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए 2,500 रुपये की मासिक सहायता और गरीब तबके की महिलाओं की शादी के वास्ते आठ ग्राम सोना देने का वादा किया गया है।

विजय ने इन महिलाओं की शादी के लिए सोने के अलावा उच्च गुणवत्ता वाली रेशम की एक साड़ी देने का भी वादा किया। उन्होंने महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के वास्ते पांच लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण और बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए माताओं को प्रतिवर्ष 15 हजार रुपये देने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन का भी आश्वासन दिया।

विजय ने प्रतिष्ठित नेता कामराज के नाम पर 100 विशेष आवासीय स्कूलों और 20 लाख रुपये तक के उच्च शिक्षा ऋण का वादा किया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मंत्रालय, एआई विश्वविद्यालय और एआई शहर की स्थापना का भी आश्वासन दिया। घोषणापत्र में कृषि कल्याण पर भी विशेष बल दिया गया है। टीवीके प्रमुख ने आश्वासन दिया है कि पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के कृषि सहकारी फसल ऋण पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे, जबकि पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 50 प्रतिशत ऋण माफी मिलेगी। इसके अलावा, पार्टी ने धान के लिए 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ने के लिए 4,500 रुपये प्रति टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया।

बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए, विजय ने पांच लाख नयी सरकारी नौकरियां सृजित करने का वादा किया। घोषणापत्र में वादा किया गया है कि बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 4,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर विचार करने और नर्सों समेत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन्होंने तमिलनाडु को नशामुक्त बनाने का वादा किया। विजय ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण, मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच और 25 लाख रुपये की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की भी प्रतिबद्धता जताई। घोषणापत्र में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 3,000 रुपये की मासिक पेंशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पट्टा नियमितीकरण और सभी घरों के लिए पाइप से शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति का वादा भी शामिल है। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा।

बालुरघाट और खड़गपुर के लिए विशेष ट्रेन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। दक्षिणी रेलवे से प्राप्त विज्ञप्ति के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन नंबर 06551/06552 एसएमवीटी बेंगलूरु - बालुरघाट-एसएमवीटी बेंगलूरु एक्सप्रेस स्पेशल जोलारपेट्टई और काटपाडी के माध्यम से चलाई जा रही है।

ट्रेन संख्या 06551 एसएमवीटी बेंगलूरु-बालुरघाट एक्सप्रेस स्पेशल (जोलारपेट्टई और काडपाडी होते हुए) 17 और 24 अप्रैल, शुक्रवार को एसएमवीटी बेंगलूरु से सुबह 8:50 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 6:00 बजे बालुरघाट पहुंचेगी। वापसी दिशा में, ट्रेन संख्या 06552 बालुरघाट-एसएमवीटी बेंगलूरु एक्सप्रेस स्पेशल काटपाडी और जोलारपेट्टई होते हुए 20 और 27 अप्रैल, सोमवार को बालुरघाट से सुबह 05:15 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 03:00 बजे एसएमवीटी बेंगलूरु पहुंचेगी। इस ट्रेन में 1 - एक थ्री-टियर कोच, 5 - स्लीपर क्लास कोच, 12 - जनरल सेकंड क्लास कोच, और 2 - सेकंड क्लास कोच (दिव्यांगजन फ्रेंडली) होंगे।

एक अन्य ट्रेन संख्या 06091 डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-खड़गपुर एक्सप्रेस स्पेशल 17 अप्रैल, शुक्रवार को सुबह 06:55 बजे डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 11:15 बजे खड़गपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 06092 खड़गपुर - चेन्नई बीच एक्सप्रेस स्पेशल 18 अप्रैल, शनिवार को खड़गपुर से दोपहर 13:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 19:30 बजे चेन्नई बीच पहुंचेगी। इस ट्रेन में 2 एसी टू टियर कोच, 2 एसी थ्री टियर कोच, 10 स्लीपर क्लास कोच , 4 जनरल सेकंड क्लास कोच और 2 सेकंड क्लास कोच (दिव्यांगजन अनुकूल) होंगे।

मुफ्त योजनाओं को लेकर

एनटीके प्रमुख सीमान ने द्रमुक और अन्नाद्रमुक पर निशाना साधा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मयिलादुथुराई। नाम तमिलर काची (एनटीके) के प्रमुख सीमान ने बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) पर तमिलनाडु में स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में सुधार करने के बजाय मुफ्त सुविधाएं बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि उनकी पार्टी 23 अप्रैल के चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो वह बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के अलावा सभी सरकारी अस्पतालों का उन्नयन करेंगे, बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएंगे और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करेंगे।

सीमान ने यहां एक चुनावी रैली में कहा, ''मुफ्तखोरी की संस्कृति को बंद कर दिया जाना चाहिए था। उन्हें (द्रविड़ पार्टियों को) लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था।'' सीमान ने द्रमुक और अन्नाद्रमुक पर आरोप लगाया कि वे कई दशकों से मुफ्त योजनाओं और विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से लोगों को लुभाकर राज्य पर शासन कर रही हैं।

उन्होंने पूछा, ''उन्हें पैसा कहां से मिलता है। राज्य का कर्ज 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।'' सीमान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली दोनों द्रविड़ पार्टियों ने तमिलनाडु की जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि द्रमुक और अन्नाद्रमुक शिक्षा को राज्य सूची में शामिल नहीं करवा सकीं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के मुद्दे और तमिलनाडु एवं केरल के बीच मुल्लापेरियार बांध के विवाद को हल नहीं कर सकीं। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होंगे।

अन्नाद्रमुक लोकसभा प्रतिनिधित्व में बदलाव के पक्ष में नहीं : कोवई सत्यन

चेन्नई। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने लोकसभा में 7.2 प्रतिशत सीट पर तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवई सत्यन ने बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर सच छिपाने' का आरोप लगाया। सत्यन ने बताया कि द्रमुक द्वारा परिसीमन पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रमुख विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने लोकसभा में 7.2 प्रतिशत सीट पर तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया। सत्यन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में पूछा, अगर सांसदों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाए, तो तमिलनाडु में सांसदों की संख्या बढ़कर 61 हो जाएगी। द्रमुक ने इसे क्यों छिपाया? उन्होंने पोस्ट में कहा, अगर झूठ पर कोई किताब लिखी जाए तो एम.के. स्टालिन ही एकमात्र ऐसे लेखक होंगे जो इसे लिखने के योग्य हैं। बेशर्म द्रमुक।

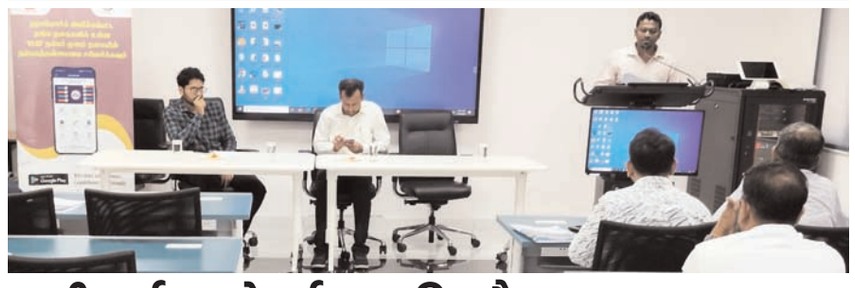

बीआईएस चेन्नई द्वारा खिलौना सुरक्षा मानक 'आईएस9873' पर 'मानक मंथन' का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। बच्चों की सुरक्षा और घरेलू खिलौना उद्योग में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), चेन्नई ने गुरुवार को एक विशेष 'मानक मंथन' कार्यक्रम का आयोजन किया। यह सत्र नए मानक आईएस 9873 (भाग 1): 2025 पर केंद्रित था, जो खिलौनों के यांत्रिक और भौतिक गुणों से संबंधित सुरक्षा पहलुओं को निर्धारित करता है।

भारतीय खिलौना निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता अपनाने और आयातित खिलौनों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। सत्र में खिलौनों के नुकीले किनारों, छोटे पुर्जों और संरचनात्मक मजबूती जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मापदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से खिलौना निर्माताओं, विक्रेताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

बीआईएस चेन्नई के निदेशक मुनिनारायण आर. ने जोर देते हुए कहा कि इन मानकों को अपनाकर भारतीय निर्माता विश्व स्तरीय और सुरक्षित खिलौने बना सकते हैं, जिससे मेड इन इंडिया उत्पादों पर उपभोक्ताओं का भरोसा और मजबूत होगा। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सत्र का संचालन नई दिल्ली से जुड़ी वैज्ञानिक सुश्री अनमोल अग्रवाल ने किया, जिसमें निर्माताओं की व्यावहारिक चुनौतियों और समाधानों पर संवाद हुआ।

चेन्नई रोड शो के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर विजय के खिलाफ केस दर्ज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय के खिलाफ चेन्नई के टी नगर इलाके में बिना अनुमति के रोड शो करके चुनावी नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई एक इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारी की शिकायत के बाद की गई। अधिकारी ने आरोप लगाया था कि विजय ने एक अलग तरह के चुनावी कार्यक्रम के लिए अनुमति मिलने के बावजूद रोड शो किया। उनके इस रोड शो को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन माना गया। पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले वेस्ट माम्बलम, नुंगमबक्कम और वेपेरी पुलिस स्टेशनों में विजय के साथ-साथ टीवीके के कई उम्मीदवारों और जिला-स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे।

अधिकारियों ने संकेत दिया कि दी गई अनुमतियां विशिष्ट, विनियमित गतिविधियों के लिए थीं, और उनमें किसी भी तरह के बदलाव (उन्हें बड़े पैमाने के रोड शो में बदलना) के लिए चुनाव अधिकारियों से पहले से अनुमति लेना आवश्यक था। इन शर्तों का पालन न करने के कथित आरोप के कारण फ्लाइंग स्क्वाड ने तत्काल कार्रवाई की। इस स्क्वाड को चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। बता दें कि इन मामलों के संबंध में विजय या टीवीके की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि वे इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनावी आचरण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गयी है : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2016 के हत्या मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को दोषी ठहराए जाने के बाद बृहस्पतिवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया। भाजपा ने कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी का नाम बदलकर अपराध और भ्रष्टाचार कर दिया जाना चाहिए। एक दिन पहले ही विशेष सांसद-विधायक अदालत ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी एवं 16 अन्य को भाजपा नेता योगेश गौदार की हत्या का दोषी ठहराया।

गौदार की 2016 में हत्या कर दी गयी थी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस को अपना नाम आईएनसी 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' से बदलकर सीएनसी 'अपराध और भ्रष्टाचार' कर लेना चाहिए।

प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बिक्री में लिप्त दस लोग गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर के कई इलाकों में प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री में कथित तौर पर लिप्त 10 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन विदेशी नागरिक जिनमें दो महिलाएं हैं, शामिल हैं। पुलिस कहा कि आरोपियों के पास से करीब 11.81 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। इनमें पांच किलोग्राम एमएमडीए, एक किलोग्राम कोकीन, 21 किलोग्राम गांजा, 19 ग्राम एक्स्टेसी की गोलियां शामिल हैं।

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण राज्य सरकार की प्राथमिकता : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाकर प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवान अथक परिश्रम, अनुशासन और जनसेवा के जज्बे के साथ हर परिस्थिति में ढाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है तथा हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शर्मा गुरुवार को राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने 77 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा में साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसालें पेश की हैं। शर्मा ने अमर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों ने आमजन की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रदेश में सुदृढ़ पुलिसिंग से समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। अच्छी कानून व्यवस्था से राजस्थान की पहचान अब एक शांतिप्रिय राज्य के रूप में बनी है। इससे बड़ी संख्या में निवेशक और पर्यटक प्रदेश में आने के उत्सुक हैं और राज्य अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग से साइबर अपराध, नशा व संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाए गए नवीन कानूनों के क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले दो वर्षों में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में 25.68 प्रतिशत, डकैती में 47.26, लूट में 50.75 तथा महिला अत्याचारों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर एक पुलिस थाना और 17 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। नकल माफिया पर कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, प्रदेश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और जिससे युवाओं का सरकार में विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रभावी कार्य कर रहा है। इससे फायर आर्म्स के उपयोग एवं उनसे होने वाली मौतों में गिरावट आई है। वहीं, साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए सभी पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना कर आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस कार्मिकों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेश के पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 8 हजार से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। साथ ही, प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय तथा 23 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि 8 पुलिस चौकियों का पुलिस थानों में क्रमोन्नयन, 1 हजार पुलिस मोबाइल यूनिट्स की तैनाती, 35 नवीन पुलिस चौकियां खोलना, कॉन्स्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के कार्मिकों के स्वीकृत सालाना वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी, पुलिस कर्मियों के मैस भत्ते की राशि में वृद्धि जैसे निर्णयों से पुलिस बल को मजबूत किया गया है।

कोटा में बस पलटने से तीन यात्रियों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोटा। अहमदाबाद से मध्य प्रदेश जा रही एक निजी बस राजस्थान के कोटा में डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, जिससे तीन यात्रियों की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जब बस पलटी, तो सामने का शीशा चकनाचूर हो गया और बस के केबिन में यात्रा कर रहे तीन व्यक्ति सड़क पर जा गिरे, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। रात करीब साढ़े 12 बजे दुर्घटना की सूचना मिलते ही कोटा शहर की पुलिस अधीक्षक (एसपी) तेजस्विनी गौतम, अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। यह दुर्घटना आरके पुरम पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले नयागांव ओवरब्रिज के पास हुई। पुलिस ने बताया कि क्षतिग्रस्त बस में कई यात्री फंस गए थे। दो घंटे से अधिक समय तक चले और लगभग देर रात ढाई बजे तक जारी रहे एक कठिन अभियान के बाद उन्हें निकाला गया।

कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने पुष्टि की कि तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 20 अन्य घायल हो गए। घायलों को तत्काल न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार हो रहा है। दुर्घटना का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि संभवतः कुछ मवेशियों के अचानक सड़क पार करने के कारण बस चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया होगा। खबरों के मुताबिक, बस में यात्रा कर रहे अधिकांश यात्री मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भिंड के रहने वाले हैं।

संस्कृति से जुड़कर सहकार के भाव को प्रबल करें : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को जालोर में जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि. के नवनिर्मित प्रधान कार्यालय का लोकार्पण किया। समारोह में राज्यपाल ने जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि. जालोर के नवनिर्मित प्रधान कार्यालय के लोकार्पण की शुभकामनाएं देते हुए सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के आम व्यक्ति के जीवन में वित्तीय महत्व के बारे में प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक छोटे उद्यमियों, कुटीर उद्योगों, किसानों, मजदूरों, फल-सब्जी के व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता देते हैं। इससे गरीब एवं मध्यम वर्ग को स्वरोजगार का मौका मिलता है। यही सहकार है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है।

राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में सहकारिता क्षेत्र में अपने जीवन के अनुभव व संस्मरण साझा करते हुए डेयरी व कृषि के व्यवसाय में सहकारी संस्थाओं का महत्व बताया।

उन्होने कहा कि राज्य में कृषि व डेयरी क्षेत्र में विकास व नवाचार हेतु सहकारिता से जुड़े संस्थानों को पारदर्शिता व कर्मठता से कार्य करने होंगे एवं इन वित्तीय संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आधिकाधिक संख्या में वंचित वर्ग के लोगों को जोड़ना होगा।

राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई जन-धन योजना के तहत कुल 56 करोड़ नवीन बैंक अकाउंट खोले गए। जिससे आमजन को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के पथ पर निरंतर अग्रसर है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में डेयरी के क्षेत्र में सहकारिता द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति व ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा भारतीय संस्कृति से जुड़कर सहकार के भाव को प्रबल करने की बात कही।

अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी, शुक्रवार को हल्की बारिश होने का अनुमान

जयपुर। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी हो सकती है। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह तक के चौबीस घंटे में राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में सबसे अधिक 42.8 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने व अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में आगामी तीन से चार दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा हालांकि 17 अप्रैल को कमजोर विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर, भरतपुर एवं बीकानेर संभाग व आसपास के क्षेत्र में कहीं-कहीं गरज के साथ आंधी व हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान है। विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री रहने का अनुमान है।

राज्य सरकार ने सवा दो साल में कर्मचारी हित में लिए अहम निर्णय : भजनलाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय है, जहां से राज्य की सभी नीतियों एवं योजनाओं की शुरुआत कर आमजन को लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो सरकारी कामकाज में तेजी आती है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता है। हमारी जिम्मेदारी है कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण कर सुशासन के संकल्प को साकार किया जाए।

शर्मा गुरुवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा और नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई कार्यकारिणी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसेवा की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केन्द्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवातीर्थ रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी द्वारा कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ाने के लिए 'मिशन कर्मयोगी' की शुरुआत की गई है। हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसके जरिए अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी चाहिए। साथ ही प्रशासन का मूल मंत्र 'नागरिक देवो भव' होना चाहिए, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में दिन-प्रतिदिन सुधार हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कार्मिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सवा दो साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों को समयबद्ध रूप से नियमित पदोन्नति दी जा रही है तथा ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। साथ ही, आरजीएचएस के तहत महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है।

शर्मा ने कहा कि बजट वर्ष 2026-27 में कार्मिकों और पेंशनर्स के हित में कई दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है, जो भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। वहीं, अधिकारियों को रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के कल्याण के लिए अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में पुत्रवधू को शामिल, एकल महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 6 चरणों में स्वीकृति तथा महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर एवं तनावमुक्त वातावरण देने के लिए 'मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन' की स्थापना जैसे प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि, बिजली, पानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना, यमुना जल समझौता, सोम-कमला-अम्बा सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का हुआ समाधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलक्टर सन्देश नायक ने राजस्व प्रकरणों से जुड़े परिवादों सहित 84 फरियादियों के परिवाद सुने, जिनमें से 10 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अन्य प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए कलक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस मौके पर हवामहल विधायक बालमुकुन्दाचार्य, सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा, किशनपोल विधायक अमीन कागजी, चौमू विधायक श्रीमती. शिखा मील बराला, जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी चौपड़ा भी मौजूद थीं।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 84 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने, पेंशन शुरू करवाने, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने, पेयजल की सप्लाई सुचारू कराने, पत्थरगढ़ी, कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क, आवासीय पट्टा बनवाने, नामांतरण जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील रहते हुए प्रकरणों का तथ्यों के आधार पर निस्तारण कराने के आदेश दिए। उन्होंने आमजन के हितार्थ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का निस्तारण मौके पर जाकर पीड़ित के समक्ष करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन के अभाव अभियोगों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन को नियमित जनसुनवाई के निर्देश दिये हैं।

पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। पशुपालन, मत्स्य एवं गौ-पालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीतारामजी भाले ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रमुख शासन सचिव ने हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम पर परिवादियों से सीधे संवाद किया।

चित्तौड़गढ़ से परिवादी संजय कुमार ने बताया कि राणा प्रताप सागर एवं बीसलपुर बांध में मत्स्य ठेकेदार लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध मत्स्य आखेट कर रहे हैं।

इसी प्रकार, अलवर के देवेन्द्र ने अपने पालतू को इलाज नहीं मिलने की शिकायत की, झुंझुनूं के अशोक कुमार ने पशुओं की दवाइयों की समस्या बताई, जबकि उदयपुर के देवी लाल ने डॉक्टरों की अनुपस्थिति की शिकायत की। दौसा के महेश ने वेटनरी कॉलेज में जमा राशि वापस नहीं मिलने तथा जयपुर के महेंद्र ने गौशाला अनुदान नहीं मिलने की समस्या बताई।

प्रमुख शासन सचिव ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण एवं लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार कोटा के नवल ने बिना अनुमति गाय को टीका लगाने से गाय के बीमार होने की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने तुरंत चिकित्सकीय टीम भेजने के निर्देश दिए गए। भाले ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि हेल्पलाइन 181 पर प्राप्त शिकायतों, सुझावों एवं समस्याओं की नियमित समीक्षा की जाए तथा कॉल रिस्पॉन्स टाइम, शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया और समाधान की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।

भाले ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा हेल्पलाइन प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप करने तथा पशुपालकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी भी हेल्पलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

एनवायरमेंटल एण्ड सोशल फ्रेमवर्क पर एडीबी की ओरिएंटेशन कार्यशाला संपन्न

जयपुर। एनवायरमेंटल एण्ड सोशल फ्रेमवर्क (ईएसएफ) पर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यशाला गुरुवार को जयपुर में संपन्न हुई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बैंक और विकास से जुड़ी अन्य एजेंसियों, विभागों, स्टेकहोल्डर्स के बीच सामाजिक एवं पर्यावर्णीय सुरक्षा उपायों और खरीद प्रक्रियाओं की समझ को सुदृढ़ करना रहा। कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्यों, मुख्य आवश्यकताओं और व्यवहारिक क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों पर की नोट स्पीच और प्रजेंटेशन हुए। प्रतिभागियों ने केस स्टडी के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। तकनीकी सत्रों का संचालन एडीबी के ऑफिस ऑफ सेफगार्ड्स के विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जिनमें कार्लीतो रुफो जूनियर और सुशाश्वती शामिल थीं। उन्होंने दस्तावेज़ीकरण, अनुक्रमण और ईएसएफ के तहत अनुपालन से जुड़े प्रश्नों पर खुली चर्चा भी कराई।

मेरिट पॉइंट क्राइटेरिया (एमपीसी) पर एक विशेष सत्र एडीबी के प्रोक्योरमेंट, पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व स्टेफान बेरसादी और सुअनीता ने किया। इस सत्र में भारत में गुणवत्ता आधारित बोली मूल्यांकन के विकसित होते दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया और खरीद प्रक्रियाओं में जोखिम मूल्यांकन तथा मूल्यांकन मानदंडों के समावेशन पर व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया गया।

ओरण के लिए कुल 3666 हैक्टेयर भूमि आरक्षित

जयपुर । पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय जनभावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने जैसलमेर जिले के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए ओरण भूमि के आरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

ओरण प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं के कारण स्थानीय लोग इन पवित्र उपवनों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन क्षेत्रों में पेड़ों को काटना या कुल्हाड़ी का उपयोग करना वर्जित है, जिससे यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र स्वतः ही सुरक्षित रहता है। राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर जिले के विभिन्न गांवों में ओरण के लिए कुल 3666.2139 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है, जिसमें रामगढ़ तहसील के ग्राम दिलावर का गांव में 124.9502 हैक्टेयर, कुछड़ी ग्राम में 1084.8043 हैक्टेयर और पूनमनगर ग्राम में 583.9876 हैक्टेयर, फतेहगढ़ तहसील के ग्राम भीमसर में 952.2752 हैक्टेयर और बींजोता में 96.7716 हैक्टेयरभूमि ओरण क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई है।

महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में परिसीमन के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होने का आश्वासन देते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की और कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

मोदी ने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पर अपने विचार रखते हुए यह भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए और इसका श्रेय वह विपक्षी दलों को भी देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, ''हमारे देश में जबसे महिला आरक्षण को लेकर चर्चा शुरू हुई है और जब-जब चुनाव आया है, जिस दल ने महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया।''

मोदी ने कहा, ''2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सब ने (2023 में) सहमति से इसे (महिला आरक्षण विधेयक) पारित किया था। किसी का राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ।'' उन्होंने कहा, ''अगर हम सब साथ में रहेंगे तो इतिहास गवाह है कि यह किसी के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, देश के लोकतंत्र और सामूहिक निर्णय के पक्ष में जाएगा। जिन्हें इसमें राजनीति की बू आ रही है। वे खुद के 30 साल के परिणामों को देख लें। उनका इसमें ही फायदा है। नुकसान से बच जाएंगे। राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। जो विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।'' उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन के लिए विधेयक एक साथ लाने पर और कुछ राज्यों के साथ भेदभाव होने संबंधी कुछ विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा, ''संविधान ने हमें यहां बैठकर देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। ना टुकड़ों में सोच सकते हैं, न टुकड़ों में निर्णय ले सकते हैं। निराधार बात है, इसमें रत्ती भर सचाई नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज सदन में कहना चाहता हूं कि दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो पश्चिम हो, छोटे राज्य हों, बड़े राज्य हों..... निर्णय प्रकिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी।''

अगर हम सब साथ में रहेंगे तो इतिहास गवाह है कि यह किसी के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, देश के लोकतंत्र और सामूहिक निर्णय के पक्ष में जाएगा। जिन्हें इसमें राजनीति की बू आ रही है। वे खुद के 30 साल के परिणामों को देख लें। उनका इसमें ही फायदा है। नुकसान से बच जाएंगे। राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। जो विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

भाजपा 'नारी को नारा बनाने' की कोशिश कर रही : अखिलेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण विधेयक के बहाने ''नारी को नारा बनाने'' की कोशिश कर रही है।

सपा प्रमुख ने महिला आरक्षण से संबंधित तीन विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन ''भाजपाई चालबाजी'' के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया, ''भाजपा इस (महिला) आरक्षण को लेकर नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही। लेकिन जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनका मान-सम्मान कैसे रखेंगे। जिस मूल संगठन से आप निकले हैं, उसमें मान-सम्मान के लिए कितनी नारी हैं?''

सपा सांसद ने कहा, ''हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा के अंदर जल्दबाजी क्यों है? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालनी चाहती है, वह जाति जनगणना को टालना चाहती है और ऐसा कर वह आरक्षण को टालना चाहती है।'' उन्होंने सरकार पर आधी आबादी में मुस्लिम महिलाओं को नहीं गिनने का आरोप लगाते हुए कहा, ''हमारी मांग है कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए।'' उन्होंने दावा किया कि भाजपा का असली लक्ष्य वोट हासिल करना और सत्ता में बने रहना है, इसलिए ये विधेयक लाये गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की यही राजनीतिक चाल है कि जब पुराने लोग समझ जाते हैं तो वे नए लोगों को लक्षित करते हैं, लेकिन वह इसमें सफल नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश कन्नौज से सपा सांसद ने सत्तारूढ़ दल पर यह भी आरोप लगाया, ''भाजपा की कमीशन खोरी और चंदा वसूली की वजह से जो महंगाई बढ़ी है उससे उनकी (महिलाओं की) रसोई सूनी हो गई है। रही-सही कसर सिलेंडर की कमी और बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी है।'' उन्होंने एनसीआर और अन्य स्थानों पर वेतन वृद्धि को लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं सहित कामगारों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि यह विधेयक इतना ही सही है तो इसे मेरठ और नोएडा के कामगारों के बीच बैठकर घोषित किया जाए कि उनके लिए इसमें क्या-क्या किया जा रहा है।

बहन से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की युवक ने हत्या की, गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चाईबासा/भाषा। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में 22 वर्षीय एक युवक ने बहन के साथ बार-बार छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि उन्हें बुधवार को सूचना मिली कि कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के चंदबुनिया गांव में कुल्हाड़ी से हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित को कुमारडुंगी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित रेनू ने इस घटना की जांच के लिए एसडीपीओ (जगन्नाथपुर) राफेल मुर्मू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने सबूत जुटाने के बाद उसी गांव के एक निवासी को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने बताया कि वह व्यक्ति नियमित रूप से उसकी बहन को छेड़ता था, जिससे वह ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया। पुलिस ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है।

बंगाल में घुसपैठियों का स्वागत करती हैं ममता : हिमंत विश्व शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कालचिनी/कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि जहां उनके राज्य और त्रिपुरा में भाजपा सरकारें बांग्लादेश से घुसपैठ की अनुमति नहीं देती हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बंगाल में उनका स्वागत करती हैं।

असम की सीमा से लगे अलीपुरद्वार जिले में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शर्मा ने यह भी दावा किया कि तृणमूल सरकार पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने की अनुमति नहीं देती है। उन्होंने आरोप लगाया, असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकारें बांग्लादेश से घुसपैठ की अनुमति नहीं देती हैं, लेकिन (मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी बंगाल में उनका स्वागत करती हैं।

शर्मा ने कहा कि अवैध आप्रवासन के कारण पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, और दावा किया कि राज्य में हिंदुओं की आबादी घट रही है, जबकि बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है।

असम के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि भाजपा पूर्वोत्तर राज्य में निश्चित रूप से जीतेगी और चार मई को चुनाव परिणाम घोषित होने पर 126 सदस्यीय (असम) विधानसभा में शतक बनाएगी।

असम में विधानसभा चुनाव नौ अप्रैल को एक ही चरण में हुए थे और मतगणना चार मई को होगी।

शर्मा ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतेगी, जहां राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने वाले हैं। यहां भी मतगणना असम के साथ ही चार मई को होगी।

दार्जिलिंग जिले के फांसिदेवा निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, असम एक छोटा राज्य है, हम वहां शतक बनाएंगे; बंगाल एक बड़ा राज्य है, हमें वहां दोहरा शतक लगाना होगा।

गुरु गोबिंद सिंह से प्रेरणा लेकर बिहार को समृद्ध बनाने के लिए काम करूंगा : सम्राट चौधरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह सिख गुरु गोबिंद सिंह से प्रेरणा लेकर बिहार और देश को समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे।

चौधरी ने यहां पटना साहिब गुरुद्वारे का दौरा किया, जो सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह से जुड़ा पवित्र स्थल है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता चौधरी ने बुधवार को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह पहली बार है, जब राज्य में भाजपा का कोई नेता शीर्ष पद पर काबिज हुआ है।

चौधरी ने कहा, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी से प्रेरित हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद बिहार के लोगों पर बना रहे और राज्य के साथ-साथ देश भी समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से लंबे समय तक किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

निशांत कुमार ने सम्राट चौधरी को बताया 'बड़ा भाई'

पटना/भाषा। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बृहस्पतिवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार बृहस्पतिवार दोपहर पहली बार जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में नई सरकार के नेतृत्व को लेकर खुलकर समर्थन जताया।

निशांत ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपना बड़ा भाई बताते हुए बधाई दी, साथ ही उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को भी शुभकामनाएं दीं। निशांत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सम्राट चौधरी बिहार को नई दिशा देंगे और वह उनके नेतृत्व में काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता व उनका पूरा सहयोग नई सरकार के साथ रहेगा। निशांत ने स्पष्ट किया कि अब वह जनता के बीच जाएंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। निशांत कुमार का यह बयान ऐसे समय आया है, जब नई सरकार के गठन के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।

मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहने की

अभिषेक बनर्जी ने शाह को चुनौती दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहने की बृहस्पतिवार को चुनौती दी।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर में एक चुनावी रैली में बनर्जी ने कहा, ''अगर आपमें हिम्मत है, तो मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहें, तब हम देखेंगे।'' उन्होंने ममता बनर्जी के चौथी बार मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में लौटने का विश्वास व्यक्त किया।

राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे। मतगणना चार मई को होगी।

भाजपा नेताओं से धमकियां मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ''हमें धमकियां मिल रही हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि तृणमूल कार्यकर्ता अपने घरों से बाहर न निकलें वरना उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यहां आकर बंगाल के लोगों को धमकाए।'' चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल में आरोप-प्रत्यारोप बढ़ने के बीच, बनर्जी ने संभावित राजनीतिक प्रतिशोध का संकेत दिया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''मैंने एक सूची तैयार की है-- ब्लॉक दर ब्लॉक, पंचायत दर पंचायत। सूद सहित हिसाब चुकता किया जाएगा।''

भारत में डोपिंग गंभीर समस्या , लेकिन इससे निपटने के लिए इच्छाशक्ति भी है : वाडा अध्यक्ष

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत में डोपिंग को गंभीर समस्या बताते हुए विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी (वाडा) के अध्यक्ष विटोल्ड बांका ने कहा कि मौजूदा डोपिंग निरोधक तंत्र को और मजबूत बनाने की जरूरत है और उन्हें भारत में इसके लिए इच्छाशक्ति नजर आती है ।

वैश्विक डोपिंग निरोधक खुफिया और जांच नेटवर्क एशिया ओशियाना चरण की यहां आखिरी कांफ्रेंस के बाद बांका ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' इसमें कोई शक नहीं कि डोपिंग की समस्या भारत में विकराल है । लेकिन मुझे इससे निपटने की इच्छाशक्ति नजर आती है लेकिन इसके लिए हमें और खुफिया जानकारी, लक्षित जांच और डोप शिक्षा का दायरा बढाने की जरूरत है ।''

भारत लगातार तीसरे साल वाडा के डोप उल्लंघन के आंकड़ों में शीर्ष पर रहा है । भारत में 2030 में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का भी भारत इच्छुक है । बांका ने आगे कहा ,'' मैं भारत से अपील करता हूं कि डोपिंग निरोधक तंत्र को और मजबूत बनाया जाये जिसमें वाडा मदद के लिए तैयार है । मेरी खेल मंत्रालय, नाडा और सीबीआई अधिकारियों से बात हुई और सभी मिलकर इस अभियान को सफल बना सकते हैं ।''

प्रदर्शन बेहतर करने वाली दवाओं (पीईडी) की अवैध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को निशाना बनाने वाले वाडा के 'आपरेशन अपस्ट्रीम' को क्या भारत में लागू किया जायेगा, यह पूछने पर उन्होंने कहा ,'' आपरेशन अपस्ट्रीम वैश्विक अभियान है ।

सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर

व्यक्ति ने 500 महिलाओं से दो करोड़ रुपए ठगे, गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल के जरिए डॉक्टर, फिल्म निर्माता, वकील, कारोबारी एवं मॉडल बनकर देशभर की 500 से ज्यादा महिलाओं से दो करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने के आरोप में 35 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अमित गोयल ने एक बयान में बताया कि जिले की साइबर पुलिस की एक टीम ने आरोपी आनंद कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसपर डेटिंग और विवाह संबंधी मंचों के माध्यम से महिलाओं को निशाना बनाकर 'रोमांस स्कैम', मोहपाश और ऑनलाइन ब्लैकमेल का एक संगठित नेटवर्क चलाने के आरोप हैं। पुलिस ने बताया कि कुमार महिलाओं से संपर्क करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के साथ-साथ डेटिंग और विवाह संबंधी ऐप' पर फर्जी पहचान के आधार पर प्रोफाइल बनाता था।

डीसीपी ने कहा, वह खुद को एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले सुस्थापित पेशेवर व्यक्ति के रूप में पेश करता था, और भरोसा जीतने और पीड़िताओं को आकर्षित करने के लिए अक्सर खुद को डॉक्टर, व्यवसायी या फिल्म निर्माता बताता था।

जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी पीड़िताओं से दोस्त के तौर पर बातचीत शुरू करता था और धीरे-धीरे कई दिनों या हफ्तों में उनके साथ भावनात्मक संबंध बनाता था और विश्वास कायम होने के बाद, वह उनके साथ निजी 'मैसेजिंग मंचों' पर जाकर बातचीत करता था और इन मंचों का इस्तेमाल कई मोबाइल नंबरों के जरिए किया जाता था ताकि पकड़े जाने से बचा जा सके। उन्होंने कहा, आरोपी ने एक ही समय में कई पीड़ितओं से समानांतर बातचीत की। उसने भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाया और पीड़िताओं को अपने भरोसे में लेने के लिए घनिष्ठता का भाव पैदा किया।

अधिकारी ने बताया कि पीड़िताओं का विश्वास जीतने के बाद, कुमार उनसे पैसे ऐंठने के लिए चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति, कारोबार में घाटा, पारिवारिक संकट या आर्थिक तंगी जैसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ता था। कई मामलों में, वह पीड़िताओं को लुभाने के लिए शादी या मॉडलिंग असाइनमेंट या प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश दिलाने जैसे आकर्षक अवसरों का भी वादा करता था। डीसीपी ने कहा कि एक मामले में, वैभव अरोड़ा नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसने एक महिला से कथित तौर पर लगभग सात लाख रुपए ऐंठ लिए।

अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने पहले एक डेटिंग ऐप पर इस महिला से दोस्ती की और बाद में शादी का वादा किया। आरोपी ने एक और फर्जी पहचान के आधार पर आईडी बनाई और इसमें खुद को कुमार का दोस्त बताते हुए महिला से परिचय किया और दावा किया कि वह उनके रिश्ते को औपचारिक रूप में तय करने में मदद करेगा।

भ्रष्टाचार, माफिया राज को लेकर

योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला बोला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रामपुरहाट (पश्चिम बंगाल)/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और माफिया राज ने पश्चिम बंगाल को पहचान के संकट में धकेल दिया है।

आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में बीरभूम जिले के रामपुरहाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के लोगों को अब तृणमूल कांग्रेस की जरूरत नहीं है और मतदाताओं से आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, पिछले 15 वर्षों से बंगाल पहचान के संकट का सामना कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस सरकार में आतंक, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और माफिया राज प्रदेश की पहचान बन गए हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि आम लोगों, खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा, लोग खौफ में जी रहे हैं। बेटियां और बहनें सुरक्षित नहीं हैं, युवाओं का कोई भविष्य नहीं है और राजनीतिक संरक्षण में माफिया पनप रहे है। भाजपा इस माफिया संस्कृति को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने से पहले के हालात की तुलना पश्चिम बंगाल से करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि उनका राज्य भी कभी लगातार दंगों, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का गवाह रहा था उन्होंने कहा, बंगाल में आज जो स्थिति दिख रही है, वह नौ साल पहले उत्तर प्रदेश में थी। वहां अराजकता, भय, दंगे, आपराधिक गिरोह और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था। विकास के लिए दिए गए धन को लूट लिया जाता था।

गाजियाबाद के गांव में भीषण आग में 150 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक

गाजियाबाद/भाषा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के एक गांव में बृहस्पतिवार दोपहर भीषण आग लगने से 150 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव में उस जगह पर भीषण आग लगने की सूचना मिली, जहां कबाड़ के निस्तारण और पुनर्चक्रण का काम होता है। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मंदार के मुताबिक, आग में 150 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गईं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन पूरे इलाके में धुएं का गुबार है।

सुविचार

मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय यह सोचें कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। शांत मन हर समस्या का हल ढूँढ लेता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

इन संकल्पों से बनेगा विकसित भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकसित कर्नाटक और विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन नौ सामूहिक संकल्पों का उल्लेख किया है, उन्हें सबको जीवन में उतारने की जरूरत है। अगर ये संकल्प सबके जीवन का हिस्सा बन जाएं तो देश में कई समस्याओं का ठोस समाधान हो जाए। प्रधानमंत्री ने पानी बचाने और उसके बेहतर प्रबंधन को सर्वोच्च स्थान देकर इसके महत्त्व को रेखांकित किया है। भारत में छोटी-बड़ी नदियों, झीलों, बावड़ियों, तालाबों आदि की गिनती करें तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसके बावजूद कई इलाकों में पेयजल की किल्लत बनी रहती है। भूजल का स्तर भी नीचे जा रहा है। देशवासियों को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हर साल पौधे लगाने की बातें खूब होती हैं, लगाए भी जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने पौधों की उचित देखभाल की जाती है और वे बड़े हो पाते हैं? प्रधानमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाकर उन पौधों को पेड़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। सबको अपनी मां के साथ गहरा लगाव होता है। अगर उक्त अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ाया जाए तो कुछ ही वर्षों में पूरा देश हरा-भरा हो सकता है। प्रधानमंत्री स्वच्छता पर बहुत जोर देते हैं। वे स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभिन्न मंचों से अपील कर चुके हैं। देश को स्वच्छ बनाने में योगदान देना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर आजादी के इतने दशक बाद भी सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी के ढेर मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल नहीं हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा 'वोकल फॉर लोकल' संबंधी आह्वान देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। हमें स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। यही वह तरीका है, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत बना सकते हैं और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देना भी 'स्वदेशी और आत्मनिर्भरता' से जोड़ता है। भारत में घूमने के लिए सुंदर जगहों की कोई कमी नहीं है। लोग इस बात को समझ रहे हैं और छुट्टियों में वहां भीड़ उमड़ रही है। प्रधानमंत्री ने किसानों से 'केमिकल फ्री' खेती का आह्वान कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। कई किसान ऐसा कर भी रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्राकृतिक खाद और कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण देना चाहिए। देश में नीम, आक, धतूरा जैसे दर्जनों पौधे हैं, जिनका सही इस्तेमाल जहरीले कीटनाशकों पर निर्भरता बहुत कम कर सकता है। सरकार पिछले कुछ वर्षों से मोटे अनाजों का महत्त्व खूब समझा रही है। इससे प्रभावित होकर लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल कर रहे हैं। ये अनाज मानव और धरती, दोनों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। योगाभ्यास और खेलकूद को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। जिन देशों में लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, लंबी उम्र तक जीते हैं, वहां अच्छे अस्पताल तो हैं ही; खेलकूद के लिए अच्छे मैदान भी हैं। जापान में बड़े शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक सुंदर बगीचे बने हुए हैं। वहां कोई व्यक्ति साइकिल चलाना चाहता है तो उसके लिए सड़कें काफी सुरक्षित हैं। क्या हम ऐसी व्यवस्था अपने देश में नहीं बना सकते? बच्चों को स्कूली दिनों में ही खेलकूद, व्यायाम और साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे वे ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और देश को सशक्त बनाएंगे। स्वस्थ लोग अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और सेवा संबंधी गतिविधियों से जुड़कर प्रशंसनीय योगदान दे पाते हैं।

ट्वीटर टॉक

हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं... नहीं सर! यह उसका अधिकार है।ङ्कङ्कहमने इसे कई दशकों तक रोक कर रखा है। आज इसका प्रायश्चित करने और उस पाप से मुक्ति पाने का मौका है।

-नरेन्द्र मोदी

राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर स्वर्गीय रामकिशोर व्यास की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। व्यास शुरू से ही समाज सेवा से जुड़े रहे और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी योगदान दिया था। उनका जन सेवा के प्रति अटूट समर्पण हमेशा प्रेरणा बना रहेगा।

-अशोक गहलोत

'राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस' के मौके पर, आयोजित समारोह में बहादुर नायकों के अदम्य साहस को श्रद्धांजलि दी गई।ङ्कङ्कअपनी बेहतरीन सेवा के लिए सम्मानित सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई!

-भजनलाल शर्मा

प्रेरक प्रसंग

मन नियंत्रण से स्वतंत्रता

एक बार शाही शिविर में एक युवा सैनिक रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के पास आया और बोला कि युद्ध और प्रशासन के दबाव में उसका मन लगातार विचलित रहता है, वह शांति नहीं पा पाता। ऑरेलियस ने उसे तुरंत कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे रात के समय शिविर की पहरेदारी करने और हर कुछ समय बाद केवल अपने विचारों को लिखने का निर्देश दिया। सैनिक ने कुछ दिनों तक यह अभ्यास किया और उसने पाया कि सबसे अधिक अशांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने भय और कल्पनाओं से उत्पन्न होती है। जब वह वापस सम्राट के पास आया, तो ऑरेलियस ने कहा कि जो मन को नियंत्रित कर सकता है, वही संसार में स्वतंत्र है। उन्होंने समझाया कि सम्राट होने के बावजूद वे स्वयं को हर दिन यह याद दिलाते हैं कि बाहरी घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं, पर हमारी प्रतिक्रिया पूर्णतः हमारे अधीन है। इस अनुभव ने सैनिक को यह बोध कराया कि मानसिक अनुशासन किसी भी पद या परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है।

सामयिक

महिला आरक्षण बिल पर राजनीतिक तूफान

रोहित माहेश्वरी

संसद के विशेष सत्र में 16 अप्रैल को महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन अहम संशोधन विधेयक पेश किये गये। इन प्रस्तावों के तहत वर्ष 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। संशोधन विधेयक में लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि वर्तमान में यह संख्या 543 है। जो विधेयक पेश किये गये हैं वो हैं, केंद्र शासित प्रदेश क़ानून (संशोधन) विधेयक 2026, संविधान (131 वां संशोधन) विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026। प्रस्ताव के अनुसार, राज्यों में अधिकतम 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें निर्धारित की जा सकती हैं। सीटों के अंतिम निर्धारण के लिए परिसीमन प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। नए प्रावधानों के तहत लोकसभा की 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन विधेयकों पर संसद में 18 अप्रैल तक विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

इन बिलों का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, एआईएमआईएम, सीपीआई एम समेत विपक्षी दलों ने विरोध किया है। विपक्ष इसको बीजेपी की चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहा है। हालांकि पीएम मोदी के दिशा निर्देशन में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं। इस दौरान सीट बढ़ाने के स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला पर चर्चा हुई, जिसमें मौजूदा सीटों को बढ़ाकर नए ढांचे में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय की जाएंगी। इससे लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर करीब 800 से ज्यादा हो सकती हैं। इस बीच दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन पर ऐतराज किया है। इसलिए सरकार अब ऐसा फॉर्मूला लाने की कोशिश कर रही है, जिससे सभी राज्यों के हितों का संतुलन बना रहे।

दरअसल, 2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 106 वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी मंजूरी दे चुकी हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था। हालांकि, यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसकी लागू होने की तारीख केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय करेगी और जरूरत पड़ने पर संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इसके तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना है। अब सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार करने की बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। इससे प्रोसेस तय समय पर पूरी हो सकेगी और आरक्षण लागू किया जा सकेगा। इसके लिए दो बिल लाए जा सकते हैं। एक बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से जुड़ा होगा। इसे पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा। इसी वजह से सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है।

महिला आरक्षण प्रस्ताव के मुताबिक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आरक्षण का ढांचा ऐसा होगा, जिसमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं है। इसी फॉर्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है, ताकि पूरे देश में एक जैसा ढांचा रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों इसके लिए कई नेताओं से बैठकें की हैं। इनमें वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी (एसपी), आरजेडी और एआईएमआईएम के नेता शामिल रहे। बीजेडी और शिवसेना (यूबीटी) से भी बातचीत हुई है, जबकि कांग्रेस से चर्चा बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यहां लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी। बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है। यहां कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती है। एमपी में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 यानी महिला सीटें होंगी। झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है।

साल 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। वर्ष 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया। इसके कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया। तीन साल बाद वर्ष 1974 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी। साल 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण लागू किया है।

13 जुलाई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बिल की कॉपी फाड़ दी। 11 दिसंबर 1998 को लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन सपा सांसद दरोगा प्रसाद स्पीकर पोडियम तक पहुंच गए। वर्ष 2000 में अटल सरकार ने पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्ष 2002 में अटल सरकार ने पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्ष 2003 में जुलाई में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। साल 2008 में मनमोहन सरकार ने 6 मई को राज्यसभा में विधेयक पेश किया। खूब हंगामा हुआ। स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया और दो तिहाई बहुमत से पारित हो गया। लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। बिल लैप्स हो गया। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में विधेयक संसद में पेश किया। कुशल प्रबंधन के चलते यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पारित हो गया। 106वा संविधान संशोधन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून बना।

विपक्ष का कहना है कि असली मसला महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन है। इसके बावजूद विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार की ओर से खास कर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से महिला आरक्षण का ऐसा माहौल बनाया गया है कि अगर विपक्ष ने इसका विरोध किया तो उसको महिला विरोधी माना जाहिए। संसद की कार्यवाही में विपक्षी पार्टियां परिसीमन की मुद्दा उठाएंगी लेकिन मजबूरी में उनको इसका समर्थन करना होगा, जैसे सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन कानून का किया था। जानकारों के मुताबिक पेश विधेयकों को पास कराना आसान नहीं होगा। ये संविधान में संशोधन के लिए विधेयक हैं, जिन्हें पास कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। इसके लिए सरकार को कुछ विपक्षी पार्टियों और ऐसी पार्टियों से बात करनी होगी, जो मौजूदा लोकसभा में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं।

विपक्ष का कहना है कि असली मसला महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन है। इसके बावजूद विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार की ओर से खास कर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से महिला आरक्षण का ऐसा माहौल बनाया गया है कि अगर विपक्ष ने इसका विरोध किया तो उसको महिला विरोधी माना जाहिए। संसद की कार्यवाही में विपक्षी पार्टियां परिसीमन की मुद्दा उठाएंगी लेकिन मजबूरी में उनको इसका समर्थन करना होगा, जैसे सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन कानून का किया था।

नजरिया

जनसंख्या बनाम विकास : लोकसभा पुनर्गठन की असली चुनौती

प्रो. आरके जैन अरिजीत

यदि इसे आम नागरिक की नजर से परखा जाए, तो इस बदलाव के भीतर कई ठोस संभावनाएं दिखाई देती हैं। सीटों में वृद्धि का मतलब है कि संसद में अधिक विविधता आएगी और अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याएं पहले से ज्यादा प्रभावी ढंग से उठ सकेंगी। ग्रामीण इलाकों, छोटे शहरों और पिछड़े वर्गों को अपनी बात रखने के लिए व्यापक मंच मिलेगा।

भारत की संसदीय व्यवस्था इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां लिया गया निर्णय आने वाले दशकों की राजनीति, नीतियों और प्रतिनिधित्व की दिशा तय करेगा। लोकसभा की सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 (815 राज्य व 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) करने का प्रस्ताव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के गणित और भूगोल-दोनों को बदलने वाला कदम है। सवाल सीधा है, पर इसका उत्तर जटिल-क्या इससे आम मतदाता की ताकत वास्तव में बढ़ेगी या बड़े राज्यों का राजनीतिक प्रभाव और गहरा होगा? यही वजह है कि यह बहस अब संसद तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के हर उस नागरिक तक पहुंच गई है, जो चाहता है कि उसका वोट सिर्फ गिना ही नहीं, बल्कि असर भी दिखाए।

सरकार का तर्क सीधा और ठोस है कि बढ़ती आबादी के साथ प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाना अब अनिवार्य हो चुका है। मौजूदा स्थिति में एक सांसद पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ है, जिससे स्थानीय समस्याएं अक्सर राष्ट्रीय बहस में दब जाती हैं। प्रस्तावित योजना के तहत सीटों को लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाकर अधिकतम 850 करने से प्रत्येक सांसद कम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे जनता और प्रतिनिधि के बीच दूरी घटेगी, संवाद सशक्त होगा और जवाबदेही बढ़ेगी। इससे नीतियों का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। साथ ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने के लिए यह विस्तार एक ठोस आधार के रूप में देखा जा रहा है, जो राजनीति में लैंगिक संतुलन को मजबूत कर सकता है।

इस प्रस्ताव का एक ऐसा पक्ष भी है, जो गहरी चिंता पैदा करता है और जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। दक्षिण भारत के राज्यों ने लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे में यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ, तो अधिक आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसका असर यह होगा कि दक्षिण के राज्यों का संसद में सापेक्षिक प्रभाव घट सकता है। यह स्थिति एक असंतुलन पैदा करती है, जहां विकास और बेहतर शासन का परिणाम राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी बनकर सामने आता है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी राज्य की मौजूदा सीटें कम नहीं होंगी, फिर भी दक्षिण के राज्यों को अपने प्रभाव में कमी की आशंका है।

यदि इसे आम नागरिक की नजर से परखा जाए, तो इस बदलाव के भीतर कई ठोस संभावनाएं दिखाई देती हैं। सीटों में वृद्धि का मतलब है कि संसद में अधिक विविधता आएगी और अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याएं पहले से ज्यादा प्रभावी ढंग से उठ सकेंगी। ग्रामीण इलाकों, छोटे शहरों और पिछड़े वर्गों को अपनी बात रखने के लिए व्यापक मंच मिलेगा। महिला आरक्षण के जरिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को नई प्राथमिकता मिल सकती है। यह बदलाव उन वर्गों के लिए अवसर का द्वार खोल सकता है, जो अब तक निर्णय प्रक्रिया में सीमित दायरे में ही रह गए थे। असल चिंता यहीं से शुरू होती है-क्या केवल सीटों की संख्या बढ़ा देने से प्रतिनिधित्व वास्तव में सशक्त हो जाएगा? यह मान लेना एक सरलीकृत दृष्टि होगी। प्रतिनिधित्व सिर्फ आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि संतुलन और न्यायपूर्ण भागीदारी का भी प्रश्न है। जब किसी एक क्षेत्र का प्रभाव असामान्य रूप से बढ़ता है, तो नीति निर्माण का झुकाव भी उसी दिशा में होने लगता है। इसका सीधा असर संसाधनों के वितरण, बजट आवंटन और विकास योजनाओं पर पड़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं और गहरी हो सकती हैं। दक्षिण के राज्यों की मुख्य चिंता यही है कि उनका आर्थिक योगदान और सामाजिक उपलब्धियां राजनीतिक फैसलों में अपेक्षित महत्व नहीं पा सकेंगी।

यहीं से एक रचनात्मक और संतुलित समाधान की मांग उभरती है, जहां विपक्ष और कई क्षेत्रीय दल इस प्रस्ताव को केवल संख्या नहीं, बल्कि व्यापक न्याय के दृष्टिकोण से देखने की बात करते हैं। उनका मानना है कि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर तय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें विकास के ठोस मानकों को भी शामिल करना जरूरी है। साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या नियंत्रण जैसे प्रयासों को प्रतिनिधित्व निर्धारण में उचित महत्व मिलना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस बात को रेखांकित करता है कि लोकतंत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि गुणवत्ता, जवाबदेही और संतुलित भागीदारी की एक मजबूत व्यवस्था भी है।

निर्णायक दौर में नीतियों की असली कसौटी सामने आती है और यह विमर्श भी उसी पर खरा उतरने की मांग करता है, जहाँ स्थायी व न्यायपूर्ण समाधान संतुलन में निहित है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, लेकिन संघीय ढांचे और राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। यदि परिसीमन में दोनों को समान महत्व मिला, तो यह बदलाव लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ और समावेशी बना सकता है, अन्यथा असंतुलन बढ़ सकता है। उनका मानना है कि परिसीमन केवल जनसंख्या पर आधारित न होकर आर्थिक योगदान, साक्षरता, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मानकों को भी महत्व दे, ताकि विकासशील राज्यों की प्रगति को उचित सम्मान मिल सके।

अब निर्णायक सवाल यह है कि अधिकतम 850 सीटों वाली लोकसभा देश को संतुलित प्रतिनिधित्व की ओर ले जाएगी या असंतुलन की ओर। यह प्रस्ताव न पूरी तरह लाभकारी है, न हानिकारक; इसका परिणाम इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

यदि सभी राज्यों की चिंताओं को स्थान देकर प्रतिनिधित्व को संतुलित ढंग से पुनर्गठित किया गया, तो यह आम नागरिक के वोट को वास्तविक ताकत दे सकता है। लेकिन यदि यह केवल जनसंख्या के गणित तक सीमित रहा, तो बड़े राज्यों का वर्चस्व बढ़ने का खतरा रहेगा। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि हर नागरिक महसूस करे कि उसकी आवाज का समान महत्व है और उसका वोट केवल संख्या नहीं, बल्कि प्रभाव का प्रतीक है।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

पश्चिम एशिया में मांग पर असर नहीं, अशोक लेलैंड ने पेश किए दो ईंधन वाले एलसीवी मॉडल

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्यिक वाहन कंपनी अशोक लेलैंड ने पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद मांग मजबूत बनी होने का जिक्र करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के कारण संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित उसके संयंत्र के उत्पादन पर असर पड़ा है।

कंपनी के अध्यक्ष (हल्के वाणिज्यिक वाहन, अंतरराष्ट्रीय परिचालन, रक्षा एवं बिजली समाधान) अमनदीप सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा हालात का वित्त वर्ष 2026-27 के प्रदर्शन पर संभावित असर का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन भारत में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के कारण लॉजिस्टिक और कलपुर्जों की आपूर्ति में कुछ बाधाएं आई हैं, जिससे मार्च में उत्पादन थोड़ा घट गया। उन्होंने कहा, हम वैकल्पिक मार्ग और लॉजिस्टिक व्यवस्था पर काम कर रहे हैं ताकि संयंत्र का संचालन सामान्य हो सके। स्थिति जल्द सुधरने की उम्मीद है।

इसके साथ ही सिंह ने कहा कि ईरान से जुड़े तनाव इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की मांग को बढ़ावा दे सकते हैं और कंपनी इस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है।

सिंह ने कहा, ''कंपनी के हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) मॉडल 'दोस्त' और 'बड़ा दोस्त' पहले से ही इलेक्ट्रिक संस्करण में उपलब्ध हैं और उनकी अच्छी संख्या में बिक्री हो रही है।''

इसी क्रम में अशोक लेलैंड ने बृहस्पतिवार को 'दोस्त' और 'दोस्त प्लस एक्सएल' के दोहरे ईंधन (सीएनजी और पेट्रोल) वाले संस्करण भी पेश किए। इन संस्करणों में ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से दोनों ईंधन के बीच 'स्विच' कर सकते हैं।

सिंह ने कहा कि मौजूदा तनाव के बावजूद खाड़ी देशों में मांग में कोई कमी नहीं आई है और ऑर्डर रद्द होने के मामले भी नहीं देखे गए हैं। हालांकि, पुर्जों की आपूर्ति में देरी के कारण उत्पादन पर असर जरूर पड़ा है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने में समय लग सकता है लेकिन संघर्ष थमने के बाद भारत से कलपुर्जों की आपूर्ति कुछ ही दिनों में बहाल की जा सकती है।

कंपनी की पश्चिम एशिया बाजार में मजबूत उपस्थिति है। यूएई के रास अल खैमा में स्थित विनिर्माण संयंत्र अशोक लेलैंड के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और अफ्रीकी बाजारों के एक गढ़ के रूप में काम करता है।

संबोधित

भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने गुरुवार को मुर्शिदाबाद ज़िले में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बेलडांगा सीट से पार्टी उम्मीदवार भरत झावर के सपोर्ट में एक रैली को संबोधित किया।

रैली

बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह ने गुरुवार को पटना में केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जश्न मनाने के लिए भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ रैली में हिस्सा लिया।

पश्चिम एशिया संघर्षः भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में 15-20 प्रतिशत की गिरावटः रिपोर्ट

नई दिल्ली/भाषा। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में 15-20 प्रतिशत की गिरावट आई है। बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। इसके अनुसार, संघर्ष के कारण पैदा हुई बाधाओं के चलते विमानन उद्योग को करीब 18,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा होने की आशंका है। 'भारत के पर्यटन, विमानन और आतिथ्य क्षेत्रों पर पश्चिम एशिया संघर्ष का प्रभाव' शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया गया कि विमानन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। एयरलाइन कंपनियों को उड़ानें रद्द करने, हवाई क्षेत्र के प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मार्ग में बड़े बदलावों का सामना करना पड़ रहा है।इन बाधाओं के कारण प्रमुख मार्गों पर उड़ान के समय में 2-4 घंटे की वृद्धि हुई है, जिसके चलते ईंधन की खपत और परिचालन लागत में भारी वृद्धि हुई है। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि एयरलाइन की परिचालन लागत में ईंधन की हिस्सेदारी 35-40 प्रतिशत होती है, और वर्तमान स्थिति ने एयरलाइन की लाभप्रदता पर दबाव डाला है।

'कॉकटेल-2' के सेट पर रश्मिका मंदाना की मस्ती

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'कॉकटेल-2' में नजर आएंगी। इस फिल्म में वे दीया नाम की लड़की का किरदार अदा कर रही हैं। हाल ही में फिल्म का नया गाना 'जब तलक' रिलीज हुआ था, यह एक मस्ती भरा बीट वाला गाना है, जिसमें शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन समुद्र किनारे डांस करते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को अभिनेत्री रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर सॉन्ग 'जब तलक' का बीटिएस वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वे अपने को-स्टार शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ खूब मस्ती करते नजर आ रही हैं। रश्मिका ने अपनी पोस्ट में बताया कि गाने की शूटिंग इटली के सिसिली में हुई थी। शूटिंग के दौरान शॉट्स के बीच में तीनों अभिनेता अचानक डांस करने लगते और छोटी-छोटी बातों पर हंसते रहते थे। रश्मिका ने लिखा कि यह अनुभव उनके लिए बहुत यादगार रहा। अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, दिया की डायरी का एक पन्ना, हमने सॉन्ग 'जब तक' गाने की शूटिंग इटली के सिसिली में की, वहां सब कुछ मजेदार था। शॉट्स के बीच में यूं ही डांस करना, हर वक्त मस्ती, छोटी-छोटी बातों पर हंसना और फिर भी पूरे स्टाइल के साथ शूट पूरा कर लेना।

अभिनेत्री ने अपने किरदार के बारे में लिखा, दिया उस समय अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल जी रही थी और जब आप फिल्म देखेंगे, तो आपको समझ आएगा क्यों यहां बहुत सारी मस्ती थी और उससे भी ज्यादा डांस।

रश्मिका ने अपने डांस के साथी, कृति और शाहिद के लिए उन्होंने लिखा, एली और कुंजी सच में डांस और शरारत के पार्टनर। मुझे नहीं लगता कि दिया, कुणाल और एली एक पल के लिए भी सीरियस रहे, तब भी जब उन्हें सीरियस होना चाहिए था।

उन्होंने आखिरी में लिखा, तुम लोग पागल हो और यही पागलपन मुझे बहुत पसंद है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। 'कॉकटेल-2' 19 जून को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म कॉकटेल-2 में रश्मिका के अलावा शाहिद कपूर और कृति सेनन भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म रोमांटिक कॉमेडी है और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देने वाली है।

'गली' सीरीज के लिए हंसिका मोटवानी ने की कड़ी मेहनत

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म और वेब सीरीज की दुनिया में किसी किरदार को यादगार बनाने के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग ही काफी नहीं होती, बल्कि उस किरदार का लुक, पहनावा और पूरा व्यक्तित्व भी उतना ही मायने रखता है। दर्शक तभी उस किरदार से जुड़ पाते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अभिनेत्री हंसिका मोटवानी ने भी अपनी आने वाली सीरीज 'गली' की तैयारी की है। उन्होंने अपने किरदार के लिए किए गए ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर खुलकर बात की। हंसिका मोटवानी जल्द ही प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली इस सीरीज में 'लैला' नाम का किरदार निभाती नजर आएंगी। इस किरदार को खास बनाने के लिए हंसिका ने काफी मेहनत की। उन्होंने कहा, ''लैला का लुक तैयार करने में काफी मेहनत लगी। यह एक बार में तय नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए कई बार ट्रायल किए गए। इस किरदार में कई अलग-अलग पहलू हैं, इसलिए उसका लुक भी उसी हिसाब से तैयार करना जरूरी था। लगभग 3 से 4 बार अलग-अलग टेस्ट करने के बाद फाइनल लुक तय किया गया।''

'चिरैया' की सफलता से गदगद हुईं दिव्या दत्ता, सोशल मीडिया पर फैंस का जताया आभार

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री दिव्या दत्ता अपने शानदार अभिनय से दर्शकों में खास पहचान रखती हैं। वे ज्यादातर ऐसे प्रोजेक्टस का हिस्सा होती हैं, जो समाज की कुरीतियों और गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालती है। इसी कड़ी में वह हाल ही में वेब सीरीज 'चिरैया' में नजर आई थीं। ओटीटी पर स्ट्रीम होने के बाद सीरीज को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसे देखते हुए अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, हमारे दर्शकों का इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन लोगों को यह सीरीज पसंद आई और जिनसे यह जुड़ गई और जिन्होंने इसे अपना प्यार दिया। उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। छह एपिसोड वाली हिंदी ड्रामा वेब सीरीज वैवाहिक दुष्कर्म और पितृसत्तात्मक दबाव के गंभीर विषय पर आधारित है। सीरीज के जरिए निर्देशक शशांत शाह ने उन कुरीतियों पर सोचने पर मजबूर किया है, जो सालों से प्रथा के तौर पर समाज में चली आ रही हैं, जिन पर आजतक किसी ने सवाल नहीं किया।

'चिरैया' की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शादी के बाद भी अपने अधिकारों और सहमति के मुद्दे पर आवाज उठाती है। यह सीरीज सीधे-सीधे पूछती है, क्या शादी करने भर से जीवन भर की सहमति मिल जाती है? क्या पति को जबरदस्ती करने का हक है? शशांत शाह द्वारा निर्देशित सीरीज में दिव्या दत्ता मुख्य भूमिका में हैं, जो कुरीति पर सवाल उठाने के साथ-साथ अपनों से ही लड़ती दिख रही हैं। वहीं, इसमें संजय मिश्रा भी अहम किरदार में हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, फैसल राशिद, टिन्नू आनंद और सरिता जोशी जैसे कलाकार भी खास भूमिकाओं में हैं।

यह सीरीज एसवीएफ एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई है और जियो हॉटस्टार पर एक्सक्लूसिव तौर पर स्ट्रीम हो रही है। निर्देशक के मुताबिक, 'चिरैया' न सिर्फ मनोरंजक है, बल्कि दर्शकों को सोचने पर मजबूर भी कर रही है कि शादी में प्यार के साथ सम्मान और सहमति कितनी जरूरी है।

कांतारा अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत का मिस्ट्री वाला वैनिटी पोस्ट, अगला कदम क्या है, सब कंफ्यूज़!

मुंबई/एजेन्सी

मुंबई अपने करियर के दमदार फेज़ के बाद, रुक्मिणी वसंत ने एक ऐसा क्रिप्टिक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है कि इंडस्ट्री में हलचल मच गई है-थोड़ा सा टीज़, लेकिन असली राज़ पूरी तरह सीक्रेट! हाल ही में एक्टर ने अपनी वैनिटी से एक शांत सा, बिहाइंड-द-सीन्स झलक शेयर की, जो साफ-साफ तो कुछ नहीं बताती, लेकिन सेट पर होने का हिंट ज़रूर देती है। फोटो खुद में सिंपल थी, लेकिन टाइमिंग ऐसी कि फैंस और इंडस्ट्री वाले दोनों ही डिटेक्टिव मोड में चले गएआखिर ये किस प्रोजेक्ट की शूटिंग चल रही है?

रुक्मिणी की ये उड़ान उनके हालिया परफॉर्मेंस की जबरदस्त तारीफ के बाद और तेज़ हो गई है, जिसे उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। स्क्रीन पर उनकी पकड़ ने उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे एक्साइटिंग टैलेंट्स में शामिल कर दिया है। उनके सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक है टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स, जिसमें वो यश के साथ नज़र आएंगी और डायरेक्शन है गीतू मोहनदास का।

फिल्म में रुक्मिणी 'मेलिसा' का किरदार निभा रही हैंएक ऐसा कैरेक्टर जो रहस्यमयी है, इमोशनल लेयर्स से भरा है और कहानी के डार्क, फेयरीटेल जैसे वर्ल्ड का अहम हिस्सा है। फिल्म 4 जून 2026 को रिलीज़ होने वाली है। इसके अलावा, वो जूनियर एनटीआर के साथ एनटीआरनील में भी दिखाई देंगी, जो प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड एक एक्शन ड्रामा है।

इस पीरियड फिल्म में उनका रोल फीमेल लीड के तौर पर कन्फर्म हो चुका है। कन्नड़ सिनेमा में भी रुक्मिणी ने केवीएन प्रोडक्शन्स के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म साइन की है, जिसे हेमंत एम. राव डायरेक्ट कर रहे हैंये उनकी तीसरी कोलैबोरेशन होगी 'सप्ता सागरदाचे एलो' के बाद। फिलहाल, रुक्मिणी ने अपने पत्ते छुपा कर रखे हैंबस एक छोटी सी वैनिटी झलक से सबको सस्पेंस में डाल दिया है और अब सबकी नज़र बस इसी पर हैआगे क्या?

'है जवानी तो इश्क होना है' : गिफ्ट पुराना लेकिन पैकेजिंग नई

मुंबई/एजेन्सी

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का पहला लुक रिलीज हो गया है। पहले लुक से फिल्म की कहानी साफ है कि पुराने गिफ्ट को नई पैकिंग के साथ सिनेमाघरों में उतारा जा रहा है। फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े तीनों के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाई गई है लेकिन फिल्म को लेकर सारा सस्पेंस पहले लुक में खुलकर सामने आ चुका है। 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन एक साथ दो-दो पत्नियों के साथ दोहरी जिंदगी जीने वाले हैं। पहली पत्नी है मृणाल ठाकुर और दूसरी हैं पूजा हेगड़े। पहले लुक को देखकर आपको गोविंदा की फिल्म 'सैंडविच' और 'साजन चले ससुराल' की याद आ जाएगी। कुल मिलाकर सलमान खान के गाने के टाइटल और गोविंदा की फिल्म की स्क्रिप्ट का मिक्स कॉकटेल दर्शकों को देखने को मिल सकता है।

गोंविदा की फिल्म सैंडविच सभी को याद होगी, जिसमें महिमा चौधरी और रवीना टंडन दो बच्चों को जन्म देती है, जिनका नाम टोनी और टुकटुक होता है। दोनों की शक्ल एक जैसी होती है क्योंकि दोनों के पिता गोविंदा ही हैं। 'है जवानी तो इश्क होना है' के लुक में 2 एआई से जनरेट बच्चे दिखाए गए हैं, जो पहले अपनी मम्मी का नाम बताते हैं और फिर पापा का। दोनों के पिता का नाम सेम है और फिर सवाल करते हैं, कहीं हमारे पिता एक ही तो नहीं।

लुक से साफ है कि वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'सैंडविच' और 'साजन चले ससुराल' से प्रेरित है। 'साजन चले ससुराल' का निर्देशन वरुण धवन के पिता डेविड धवन ने किया था और इस फिल्म का निर्देशन भी वही कर रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि डेविड धवन की फिल्मों में कॉमेडी की कमी नहीं होती।

उनकी फिल्में दर्शकों को खुलकर हंसने पर मजबूर कर देती हैं। उम्मीद है कि वरुण धवन की फिल्म पर्दे पर वहीं कमाल कर पाए, जो गोविंदा की फिल्में करती थीं।

नीना गुप्ता ने गजराज राव संग तस्वीर साझा कर जाहिर की दिल की बात, बोलीं- 'फिर साथ काम करने का इंतजार'

मुंबई/एजेन्सी

फिल्मी दुनिया में कुछ जोड़ियां ऐसी बन जाती हैं, जिन्हें दर्शक लंबे समय तक याद रखते हैं। ऐसी ही एक जोड़ी है, अनुभवी अभिनेत्री नीना गुप्ता और अभिनेता गजराज राव की। इस कड़ी में नीना गुप्ता ने एक खास तस्वीर साझा की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने अपनी दिल की बात जाहिर की, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नीना गुप्ता द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में दोनों कलाकार बेहद सादगी के साथ कैमरे के लिए पोज देते नजर आ रहे हैं।

नीना गुप्ता ने प्रिंटेड साड़ी पहन रखी है, वहीं गजराज राव भी अपने खास स्टाइल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ब्लैक कलर की नेहरू जैकेट पहनी हुई है। इस तस्वीर को साझा करते हुए नीना गुप्ता ने लिखा, ''मैं गजराज राव के साथ दोबारा काम करने का इंतजार कर रही हूं।''नीना गुप्ता के पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दी।एक यूजर ने लिखा, ''आप दोनों को फिर साथ देखने का इंतजार है, क्या कमाल की जोड़ी है।''दूसरे यूजर ने लिखा, ''बधाई हो वाली केमिस्ट्री आज भी याद है, फिर से साथ आओ प्लीज।''अन्य यूजर्स ने लिखा, ''आप दोनों साथ में स्क्रीन पर जादू कर देते हैं'', ''गजराज राव के साथ आपकी जोड़ी सबसे अलग लगती है'', ''जल्दी कोई नई फिल्म लेकर आइए साथ में प्लीज'', ''ओल्ड इज गोल्ड आप दोनों की जोड़ी हमेशा सुपरहिट रहेगी।''बता दें कि नीना गुप्ता और गजराज राव की जोड़ी को सबसे ज्यादा पहचान साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'बधाई हो' से मिली थी। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, सान्या मल्होत्रा झ्रझ्रऔर दिवंगत सुरेखा सीकरी जैसे कलाकार भी नजर आए थे। इस हिट जोड़ी ने साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में भी काम किया था, जिसमें उन्होंने रूढ़िवादी माता-पिता की भूमिका निभाई थी। नीना गुप्ता के साथ काम करने को लेकर एक इंटरव्यू में गजराज राव ने कहा था, ''मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करने में सहज महसूस करता हूं और उनके साथ आगे भी काम करना पसंद

अक्षय कुमार ने असरानी को किया याद

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता अक्षय कुमार दर्शकों के लिए अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' पेश करने के लिए पूरी तैयार है। इस फिल्म में उनके साथ वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, मिथिला पालकर और असरानी अहम भूमिका में नजर आएंगे। इस बीच अक्षय कुमार ने दिवंगत अभिनेता असरानी के साथ अपने लंबे सफर को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट साझा किया। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर असरानी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में दोनों कुर्सियों पर बैठे नजर आ रहे है और कुछ पढ़ते दिख रहे है। इस तस्वीर के साथ अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, ''कभी-कभी एक तस्वीर सिर्फ यादों का टुकड़ा नहीं होती। एक पूरी यात्रा को समेटती है। ये तस्वीर हमारी 'भूत बंगला' की शूटिंग से है। असरानी जी के साथ ये मेरी दूसरी और आखिरी फिल्म थी।''

कुल 12 फिल्में हमने साथ की और हर एक में मैंने उनसे कुछ नया सीखा। हर बार यह एक मास्टरक्लास थी। अक्षय कुमार ने अपने पोस्ट में बताया, ''मैंने असरानी के साथ कुल 12 फिल्मों में काम किया है। हर बार उनसे बहुत कुछ नया सीखा। हर बार मास्टरक्लास जैसा था।'' अक्षय कुमार ने असरानी की सबसे बड़ी खासियत के बारे में बात करते हुए कहा, ''जब वह परदे पर कॉमेडी करते थे, तो सब बहुत आसान लगता था। लेकिन असल में लोगों को हंसाना एक मुश्किल कला है, जिसे हर कोई नहीं कर सकता। असरानी कॉमेडी के उस्ताद थे और उनकी जगह लेना किसी के लिए आसान नहीं है।''

अक्षय कुमार ने आगे कहा, मेरे लिए 'भूत बंगला' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है। यह मेरे लिए एक याद, एक श्रद्धांजलि और एक सम्मान है, जो मैं असरानी को देना चाहता हूं। असरानी हमेशा यादों में जिंदा रहेंगे और उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।'' असरानी का निधन अक्टूबर 2025 में 84 वर्ष की उम्र में हुआ था, लेकिन उनकी कला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।

'पर्ल्स ऑफ आइरिस रिपेयर' के लिए पुरस्कार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। नेत्र देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल्स के दो प्रतिष्ठित नेत्र रोग विशेषज्ञों डॉ. अथिया अग्रवाल और डॉ. सूजन जैकब को उन्नत नेत्र शल्य चिकित्सा तकनीकों पर उनकी शैक्षिक फिल्मों के लिए वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी (एएससीआरएस) के 44वें फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

इस महोत्सव में आयोजित होने वाले त्वरित वीडियो सत्रों में शल्य चिकित्सा संबंधी सुझाव, नवीन तकनीकें, जटिलताओं का प्रबंधन और नैदानिक अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले परिवर्तनकारी उपकरण जैसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण क्षणों को प्रदर्शित किया गया। डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल की निदेशक डॉ. अथिया अग्रवाल ने अपनी प्रस्तुति पर्ल्स ऑफ आईरिस रिपेयर के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। डॉ. अथिया अग्रवाल एक प्रमुख नेत्र शल्य चिकित्सक और नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं तथा डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

इसी फिल्म महोत्सव में, डॉ. अग्रवाल रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया फाउंडेशन की निदेशक और प्रमुख डॉ. सूजन जैकब ने केराटोप्लास्टी में रीबबलिंग शीर्षक से अपने सर्जिकल वीडियो प्रस्तुति के लिए उपविजेता पुरस्कार जीता। इस अवसर पर डॉ. आथिया अग्रवाल एवं डॉ सूजन जैकब ने कहा कि यह सम्मान पाकर वह दोनों बेहद गौरवान्वित है यह मरीजों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें निरंतर सीखने और ज्ञान साझा करने के महत्व को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि एएससीआरएस जैसे वैश्विक मंच पर सम्मानित होना उन दोनों के लिए गौरव की बात है। यह पुरस्कार उन दोनों के मार्गदर्शकों, सहकर्मियों और उन मरीजों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है जो उन्हें प्रतिदिन प्रेरित करते हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री गुप्ता ने व्यापारियों, राजस्थानियों से की मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयम्बटूर। यहां के आरएसपुरम् स्थित राजस्थानी निवास में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्थान संघ एवं राजस्थान फाउन्डेशन द्वारा संयुक्त तत्वावधान में बिज़नेस कम्युनिटी के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात की।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने सभी से मुलाकात कर कहा कि कोयंबटूर के राजस्थानी समुदाय के साथ मेरी बातचीत बहुत ही सार्थक रही। उनकी यह यात्रा इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे विश्वास और कड़ी मेहनत पर आधारित उद्यमशीलता, पीढ़ियों का कायाकल्प कर सकती है और राष्ट्र-निर्माण में योगदान दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उद्यमशीलता की इस भावना को नए अवसरों, व्यापार करने में अधिक सुगमता और एक विकसित भारत के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। मैं समुदाय के प्रत्येक सदस्य से इस प्रगति की यात्रा का हिस्सा बनने की अपील करता हूँ।

उन्होंने हाल के तमिलनाडु चुनाव में भाजपा व एनडीए को मत देने की विनंती की।

इस कार्यक्रम मे सबका स्वागत राजस्थान संघ के अध्यक्ष संतोष मुंद्ड़ा और राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष पटवारी ने किया। संचालन आकांगशा पुगालिया ने किया। रेखा गुप्ता का सम्मान किया गया। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के कोयम्बटूर इकाई के अध्यक्ष राजेश ने कोयम्बटूर इंडस्ट्रीज की ओर से ज्ञापन सौंपा।

विजय की 'लॉटरी राजनीति':

टीवीके के घोषणापत्र पर उठे सवाल, 6 लाख करोड़ के वादों ने बढ़ाई आर्थिक चिंता : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) द्वारा जारी चुनावी घोषणापत्र विवादों के घेरे में आ गया है। विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे लॉटरी वाली राजनीति करार देते हुए राज्य की आर्थिक स्थिति पर इसके पड़ने वाले गंभीर प्रभावों की चेतावनी दी है। भाजपा के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने चिंता जताते हुए कहा कि टीवीके के घोषणापत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए मासिक नकद सहायता, मुफ़्त एलपीजी सिलेंडर, दुल्हनों के लिए सोना, और पूर्ण कर्ज माफी जैसे लोकलुभावन वादों की झड़ी लगा दी गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन वादों को पूरा करने के लिए कम से कम 6 लाख करोड़ की भारी-भरकम राशि की आवश्यकता होगी। आलोचकों का तर्क है कि यह राशि तमिलनाडु की वर्तमान आर्थिक हकीकत से कोसों दूर है।

आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है। अनुमान है कि 2026-27 तक राज्य की कुल देनदारियां 10.71 लाख करोड़ के पार पहुंच सकती हैं। ऐसे में इतने बड़े वित्तीय बोझ वाले वादे करना राज्य को दिवालियापन की ओर धकेलने जैसा है। प्रसाद ने कहा कि चुनावी घोषणापत्र कोई सिनेमा की पटकथा नहीं है। विजय का घोषणापत्र मतदाताओं को केवल 'लॉटरी' का लालच देकर वोट बटोरने का एक प्रयास है। इसमें कृषि या ग्रामीण विकास के लिए कोई ठोस रोडमैप नहीं है।

प्रसाद का कहना है कि विजय अभी एक परिपक्व जन नेता के रूप में नहीं उभरे हैं और उनके वादे किसी जादू की छड़ी की तरह हैं जो धरातल पर संभव नहीं। सत्ताधारी द्रमुक पर भी 2021 में ऐसे ही वादे करने के बाद मुकरने का आरोप लगता रहा है। अब विजय भी उसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं।

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जहाँ एक तरफ एनडीए 'डबल इंजन' सरकार के माध्यम से विकास और वित्तीय अनुशासन की बात कर रही है, वहीं विजय की टीवीके और सत्ताधारी द्रमुक जैसे दल मुफ्त की योजनाओं के सहारे मतदाताओं को लुभा रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु की जनता इस 'फिल्मी जज्बातों' वाले घोषणापत्र पर भरोसा करती है या वित्तीय स्थिरता और विकास के एजेंडे को चुनती है। चुनाव आयोग से भी मांग की जा रही है कि वह ऐसे वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदार घोषणापत्रों पर नकेल कसने के लिए दिशा-निर्देश जारी करे।

उमरावदेवी धींग की स्मृति में हुआ नवकार जाप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। राजस्थान में उदयपुर जिले के ग्राम बंबोरा में गुरुवार को श्राविकारत्न उमरावदेवी धींग के दसवें स्वर्गारोहण दिवस पर नवकार महामंत्र जाप का आयोजन हुआ। संयोजक उत्कर्ष ने बताया कि कार्यक्रम में डॉ. दिलीप धींग की पुस्तक 'नानेश नेमी निर्झर' की प्रभावना की गई। साधुमार्गी जैन श्राविका संघ की पूर्व अध्यक्ष सुशीला जारोली ने वरिष्ठ श्राविका मानवती कदमालिया को पुस्तक की प्रति भेंट की। सबको पुस्तक और स्वाध्याय की प्रेरणा दी गई।

एडवोकेट अतुल शाह ने बताया कि 35 साल पहले डॉ. धींग ने अपनी माता श्राविकारत्न उमरावदेवी की प्रेरणा से आचार्य नानेश और उनके जीवनी-लेखक डॉ. नेमीचंद के साहित्य पर यह कार्य किया था। इसमें आचार्य जवाहर की 150वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा पिछले साल जारी स्मारक सिक्के, डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण की छवियां भी अंकित हैं। नवकार और पुस्तक महिमा को समर्पित इस कार्यक्रम में प्रेमकुँवर राणावत, रेखा जारोली, कौशल्या वया, इंद्रा पितलिया, शांता नागोरी सहित अनेक श्राविकाएँ उपस्थित रहीं। सुरेशचंद्र धींग ने आभार जताया।

एसआरएमसीपीटी में इंटरनेशनल फिजियो थेरेपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। कट्टानकुलथुर स्थित एसआरएम कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी द्वारा एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया इसका मुख्य विषय था वैश्विक फिजियोथेरेपिस्ट का निर्माण स्थिरता, मूल्य और मानक। इस सम्मेलन में दुनिया भर से एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इस सम्मेलन में स्वास्थ पेशेवरों के बीच विचारों, संस्कृतियों और क्लिनिकल अनुभवों के आदान-प्रदान किया गया।

यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप आयोजित किया गया, विशेष रूप से अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा असमानताओं में कमी और लक्ष्यों के लिए साझेदारी। प्रत्येक सत्र और संवाद ने एक समावेशी, सुलभ और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के साझा संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई गई। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए, एसआरएम कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रोफेसर और डीन, प्रो. वीरगौतमन ने कहा कि यह सम्मेलन फिजियोथेरेपी समुदाय में अकादमिक उत्कृष्टता और सार्थक वैश्विक सहभागिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एसआरएमआईएसटी के प्रो वाइस चांसलर , डॉ. नितिन एम. नागरकर ने कहा कि आज के फिजियोथेरेपिस्ट को सीमाओं से परे जाकर सेवा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सही कौशल, मूल्य और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ, वे दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

एसआरएमएमसीएचआरसी की डीन (मेडिकल), डॉ. जयंती आर ने फिजियोथेरेपी के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में फिजियोथेरेपी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ऐसे मंच अकादमिक ज्ञान और क्लिनिकल अभ्यास के बीच की दूरीको कम करने में सहायक होते हैं। सम्मेलन के दौरान वैश्विक विशेषज्ञों ने उभरते रुझानों, शोध प्रगति और टिकाऊ स्वास्थ्य पद्धतियों पर अपने विचार साझा किए। चर्चाओं का केंद्र एक ही विचार रहा ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट तैयार करना, जो क्लिनिकल विशेषज्ञता के साथ मजबूत मूल्यों, साक्ष्य-आधारित अभ्यास और वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाएं।

मानव जीवन का पहला सुख है निरोगी काया : ब्रह्मर्षि भानुप्रताप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के गांधीनगर स्थित आर्का महागणपति देवस्थान भवन में ग्वालियर के बालाजी मठ मंदिर धार्मिक एवं पुण्यार्थ लोक न्यास के अध्यक्ष ब्रह्मर्षि भानुप्रताप दुबे ने अपने प्रवचन में कहा कि मानव जीवन का पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी जीवन यापन के लिए मनुष्य का आहार, विहार, नियम जरूरी है।

रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोए रहना जीवन की गति में अवरोधक हैं। भौतिक संसाधनों की भरमार या धन की अधिकता हमको स्वस्थ दिनचर्या नहीं दे सकती, उसके लिए देवतुल्य कार्य करना होंगे। ब्रह्ममुहूर्त में जागना, नित्य व्यायाम करना, संयमित आहार लेना, परमात्मा जिनकी वायु पर हम जीवित हैं उनका हृदय से चिंतन करना, सत्कर्म के प्रति उत्साहित रहना, व्यसनों से बचना यही मानव की ज्ञान इंद्रियों की जागृति है जिसके बल पर जीवन टिका है।

जिनवाणी श्रवण हमारा प्रथम और पवित्र कर्तव्य होना चाहिए : साध्वीश्री नमन

सुनते वक्त समानांतर जाप जपना, स्वाध्याय करना, माला गिनना, ये सभी जिनवाणी की आसातना है। कुछ पल के लिए हम संसार और संसार के सारे व्यवहार को भूल जाएं और स्वयं को वाणी में एकमेक कर लेवें तभी इस वाणी के रहस्य और लाभ आदि से साक्षात्कार कर सकेंगे।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अलसूर के तत्वावधान में महावीर भवन में आयोजित प्रवचन में साध्वीश्री नमनजी ने कहा कि जिनवाणी श्रवण हमारा प्रथम और पवित्र कर्तव्य होना चाहिए और जब जिनवाणी बरस रही हो तो एकाग्र होकर सुनना चाहिए। सुनते वक्त समानांतर जाप जपना, स्वाध्याय करना, माला गिनना, ये सभी जिनवाणी की आसातना है। कुछ पल के लिए हम संसार और संसार के सारे व्यवहार को भूल जाएं और स्वयं को वाणी में एकमेक कर लेवें तभी इस वाणी के रहस्य और लाभ आदि से साक्षात्कार कर सकेंगे।

प्रवचन प्रारंभ करते हुए साध्वीश्री विहांशीजी ने कहा कि हम सम्यक श्रोता बने जो जिनवाणी को दूध और शक्कर की तरह स्वयं में घुला ले। जिनवाणी श्रवण कर प्रभावित होने की अपेक्षा हम भावित हो। हमारा वैराग्य श्मशानी वैराग्य नहीं हो जो क्षणिक होता है। हमारी विचारधारा ही बदल जानी चाहिए। साधु को देखकर खुश हो और धर्म स्थान में आने का पक्का नियम होना चाहिए। यहां की तरंगें विशिष्ट होती है और हम आएंगे तो ही हमारी अगली पीढ़ी हमारा अनुसरण करेगी। जीवन में मौन को विशिष्ट स्थान दें। समभाव रखें और काम हो तो ही बोलें और मधुर बोलें।ङ्क संघ के मंत्री अभय कुमार बांठिया ने बताया कि साध्वीश्री विहांशीजी का वर्षीतप चल रहा है। धनपतराज बोहरा ने अतिथियों का स्वागत किया। संघ के तत्वावधान में कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ द्वारा संचालित शिविर में 76 बच्चों ने ज्ञानार्जन किया और सामूहिक कक्षा में साध्वी वृंद के सान्निध्य में 14 स्वप्नों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

'शीघ्र ही शुरू होगी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन'

कर्नाटक श्वेतांबर जैन फोरम ने अल्पसंख्यक विभाग की सचिव से की मुलाकात

अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों और अल्पसंख्यकों से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी दी। डीसी जैन और कोमल जैन ने कर्नाटक में संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को लेकर जैन समाज के सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय कर्नाटक श्वेतांबर जैन फोरम (केएसजेएफ) के संस्थापक सिद्धार्थ जैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक सरकार के अल्पसंख्यक विभाग की सचिव डॉ. शामला इकबाल से मुलाकात की तथा अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं से अवगत कराया। सिद्धार्थ जैन ने मुलाकात की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। रेशु बैद और भावना मकाना ने श्वेतांबर जैन समाज की मांगों का विस्तृत विवरण पेश किया। हितेश गिरिया ने अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों और अल्पसंख्यकों से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी दी। डीसी जैन और कोमल जैन ने कर्नाटक में संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को लेकर जैन समाज के सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया। डॉ. शामला इकबाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जैन धार्मिक संपत्तियों के निर्माण और मरम्मत के लिए सब्सिडी की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जाएगा और इसके लिए उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। उन्होंने कहा कि जैन साधु-संतों को अब सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों में ठहरने की अनुमति प्रदान की जाएगी, ताकि विहार के दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो ऐसा प्रयास रहेगा। डॉ. शामला ने बताया कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इस नंबर पर कॉल करते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न पर तुरंत रोक लगे। बैठक में सचिव ने श्वेतांबर जैन समाज से जुड़े अन्य विषयों पर भी निरंतर सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जैन समाज के कैलाश सांखला, पृथ्वीराज मेहता, डॉ. भीखमचंद, सुरेश चावत, लाभेश जैन, उषा जैन, किशोर शाह, नितेश राठौड़, गौतम ओस्तवाल, गौतम मुथा, अशोक जैन, कविश नवेदिया, विपिन संघवी सहित विभिन्न संघों के अनेक प्रतिनिधि शामिल थे।

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अर्पिता घोष बालुरघाट से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अपने डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के दौरान।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.